

सुरत गुजरात से प्रकाशित, मुंबई, उत्तरप्रदेश, बिहार, राजस्थान, मध्यप्रदेश, उत्तरांचल, उत्तराखंड, दिल्ली, हरियाणा में प्रकाशित

सुरत-गुजरात, संस्करण बुधवार 18 फरवरी 2026 वर्ष-9,अंक-26 पृष्ठ-08 मूल्य-01 रूपये

Website : www.krantisamay.com & epaper.krantisamay.com



www.facebook.com/krantisamay1



www.twitter.com/krantisamay1

अप्रैल में हो सकता है

बंगाल सहित चार राज्यों

में विधानसभा चुनाव की

घोषणा मार्च में संभव

नई दिल्ली (एजेंसी)। पश्चिम बंगाल समेत 4 राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश में विधानसभा चुनावों की घोषणा अगले महीने यानी मार्च में हो सकती है। अप्रैल में इन राज्यों में विधानसभा के चुनाव कराये जा सकते हैं। अप्रैल में पश्चिम बंगाल के अलावा असम, तमिलनाडु, केरल और पुडुचेरी में अलग-अलग तारीखों पर विधानसभा चुनाव हो सकते हैं। अधिकारियों ने मंगलवार को यह जानकारी दी है। उन्होंने कहा कि निर्वाचन आयोग विधानसभा चुनावों की तारीखों की घोषणा 'मार्च के मध्य में किसी समय' एक साथ करेगा। चुनाव अप्रैल में अलग-अलग तारीखों पर हो सकते हैं। 5 विधानसभाओं का कार्यकाल मई और जून में अलग-अलग तारीखों पर खत्म हो रहा है। केंद्रशासित प्रदेश पुडुचेरी की विधानसभा का 5 साल का कार्यकाल 15 जून को खत्म होगा। असम, केरल, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल विधानसभा का कार्यकाल क्रमशः 20, 23, 10 और 7 मई को खत्म हो रहा है।

सुप्रीम कोर्ट में लालू यादव

की सजा निलंबन की

याचिका पर सुनवाई टली

नई दिल्ली (एजेंसी)। बिहार के पूर्व सीएम लालू प्रसाद यादव के देवघर जिला कोषागार घोटाले मामले में मिली सजा के निलंबन को चुनौती देने वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में मंगलवार को सुनवाई टल गई। अब इस मामले में सुनवाई अप्रैल में होगी। सजा के निलंबन को चुनौती देने के मामले में मंगलवार को जस्टिस एफएम सुंदरेश और जस्टिस एनके सिंह की बेंच में सुनवाई हुई। इस दौरान सीबीआई के वकील ने कहा कि ये सभी आरोपी अवैध रूप से बाहर हैं और ये दोषसिद्धि के बाद की स्थिति है। सीबीआई की ओर से चारा घोटाले में सजा पाए आरोपियों के सजा से निलंबन को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई गई थी। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक देवघर जिला कोषागार घोटाले में साल 1990 और 1994 के बीच देवघर ट्रेंजरी से 89 लाख रुपए की कथित हेराफेरी शामिल है, जिसमें पूर्व केंद्रीय रेल मंत्री और आरजेडी प्रमुख लालू यादव को इस घोटाले में दोषी ठहराया गया था। साल 2017 में सीबीआई की स्पेशल कोर्ट ने उन्हें 3.5 साल की सजा सुनाई थी। इसके साथ ही देवघर जिला पश्चातन विभाग को दवा और अस्पताल के लिए सामानों की खरीद के लिए 4.7 करोड़ रुपए दिए गए थे, लेकिन आरोप लगा कि घोटाला करने वालों ने फेक रसीद के सहारे 89 लाख रुपए से अधिक की राशि निकाल ली। इस केस में लालू यादव पर आरोप है कि उन्होंने पद का दुरुपयोग किया और मामले की जांच के लिए आई फाइल को अपने पास रोके रखा।

रोहतक में दिनदहाड़े गैंगवार:

आईजी ऑफिस के पास युवक

पर बरसाई 22 गोलियां

रोहतक (एजेंसी)। हरियाणा के रोहतक में सरेराह हुई अंधाधुंध फायरिंग की वारदात ने शहर की सुरक्षा व्यवस्था को हिलाकर रख दिया है।आईजी कार्यालय से महज कुछ ही दूरी पर स्थित दिल्ली बाईपास के पास अज्ञात हमलावरों ने दिनेश उर्फ गोगा नामक युवक पर ताबड़तोड़ गोलियां बरसा दीं।हमलावरों की दुस्साहस का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि मृतक के शरीर पर करीब 22 गोलियां दामगी गईं, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई।व्यस्त सड़क पर आनकत हुईइस फायरिंग से राहगीरों में भगदड़ मच गई और पूरे इलाके में दहशत का माहौल पैदा हो गया। सूचना मिलते ही पुलिस की भारी नफरी मौके पर पहुंची और इलाके की घेराबंदी की। जांच के दौरान घटनास्थल से पुलिस को गोलियों के करीब 28 से 30 खाली खोल बरामद हुए हैं, जो हमले की भयावहता को दर्शाते हैं। मृतक दिनेश का भी अपराधिक रिकॉर्ड बताया जा रहा है। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक, हमलावर एक तेज रफतार वाहन में आए थे और वारदात को अंजाम देकर आसानी से फरार हो गए। इस हत्याकांड के कुछ ही देर बाद सोशल मीडिया पर एक पोस्ट वायरल हुई, जिसने पुलिस और प्रशासन की नींद उड़ा दी है। वायरल पोस्ट में जय भोले की लिखते हुए इस हत्या की जिम्मेदारी ली गई है। दावा किया गया है कि दिनेश गोगा की हत्या अमेरिका में बैठे कुख्यात गैंगस्टर हिमांशु भाऊ और मोस्ट वांटेड नीरज फरीदपुरिया के इशारे पर की गई है। पोस्ट में बेहद आक्रामक लहजे में लिखा गया है कि अभी 2-4 कीड़े-मकोड़े और बाकी हैं, जिनका समय आ गया है। इसके साथ ही पोस्ट में कुछ पुलिसकर्मियों पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगाते हुए कहा गया कि वे ईमानदार खाकी का सम्मान करते हैं, लेकिन कुछ भ्रष्ट अधिकारियों के कारण उन्हें ऐसे कदम उठाने पड़ रहे हैं। फिलहाल, पुलिस सीसीटीवी फूटेज खंगाल रही है और सोशल मीडिया पोस्ट की सत्यता की जांच के साथ हमलावरों की तलाश में जुटी है।

6 अदालतों को बम से उड़ाने की धमकी

गांधीनगर (एजेंसी)। गुजरात में स्कूलों के बाद अब अदालतों के बम धमकी से उड़ाने की धमकी मिली है। मंगलवार को वडोदरा, वलसाड, गांधीनगर और अहमदाबाद समेत 6 जिला कोर्ट को धमकी वाला ईमेल मिला। इसके बाद इन कोर्ट में अफरा-तफरी का माहौल हो गया। जानकारी मिलने पर पुलिस, बॉम्ब स्कॉड और रिनफर्ड डेंग्स की टीमें कोर्ट पहुंची। सभी कोर्ट कंपैस खाली कराए गए, इसके बाद जांच की गई। हालांकि किसी भी कोर्ट में कुछ भी संदिग्ध नहीं मिला। 16 फरवरी को भी गुजरात के 40 स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी मिली थी। वडोदरा के 25 स्कूलों और अहमदाबाद के 15 स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी भरे पत्र मिले थे। इनमें मोदी-शाह की निशाना बनाने की बात लिखी थी।

इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट: जनता के लिए हो एआई का इस्तेमाल: पीएम मोदी

नई दिल्ली (एजेंसी)। नई दिल्ली, (इएमएस)। दिल्ली के भारत मंडपम में चल रहे पांच दिवसीय इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट 2026 के दूसरे दिन मंगलवार को पीएम मोदी ने कहा कि इस शिखर सम्मेलन का उद्देश्य यह पता लगाना है कि एआई का इस्तेमाल सभी के लाभ के लिए कैसे किया जा सकता है। पीएम मोदी ने एक्स पर लिखा कि बुद्धिमत्ता, तर्कसंगतता और निर्णय लेने की क्षमता विज्ञान और प्रौद्योगिकी को जनता के लिए उपयोगी बनाती है।

सोमवार से शुरू हुए इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट 2026 में राष्ट्राध्यक्ष और सरकार प्रमुखों, मंत्रियों, वैश्विक प्रौद्योगिकी नेताओं, प्रख्यात शोधकर्ताओं, बहुपक्षीय संस्थानों और उद्योग जात के हितधारकों को एक साथ लाया गया ताकि समावेशी विकास को आगे बढ़ने, सार्वजनिक प्रणालियों को मजबूत करने और सतत विकास को सक्षम बनाने में एआई की भूमिका पर विचार-

विमर्श किया जा सके। यह पहली बार है कि इस मुद्दे पर इतने बड़े पैमाने पर वैश्विक सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है।

मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक यह समिट 20 फरवरी को समाप्त होगी, इसमें 100 से ज्यादा सरकारी प्रतिनिधि भाग लेंगे, जिनमें 20 से ज्यादा राष्ट्राध्यक्ष, 60 मंत्री और उप मंत्री शामिल हैं, साथ ही सीईओ, संस्थापक, शिक्षाविद, शोधकर्ता, सीटीओ और परोपकारी संगठनों समेत 500 से ज्यादा वैश्विक एआई नेता भी शामिल हो रहे हैं। 19 फरवरी को पीएम मोदी उद्घाटन भाषण देंगे, जो वैश्विक सहयोग की दिशा तय करेगा और समावेशी एवं जिम्मेदार एआई के लिए भारत के दृष्टिकोण को प्रस्तुत करेगा। शिखर सम्मेलन का एक प्रमुख आकर्षण तीन प्रमुख वैश्विक प्रभाव चुनौतियां हैं - एआई फॉर ऑल, एआई बाय हर और युवआई जिनका समापन फाइनलिस्टों की घोषणा और ग्रैंड फिनाले शोकेस के साथ होगा।

इन चुनौतियों के लिए 60 से ज्यादा देशों से 4,650 से अधिक आवेदन प्राप्त हुए, जो मजबूत अंतरराष्ट्रीय भागीदारी को दर्शाते हैं और जिम्मेदार और स्केलेबल एआई नवाचार के लिए एक विश्वसनीय वैश्विक केंद्र के रूप में भारत के उदय की निर्माताओं और उद्योग जगत के नेताओं द्वारा किए गए एक कठोर बहुस्तरीय मूल्यांकन के बाद, तीनों श्रेणियों में शीर्ष 70 टीमें को फाइनलिस्ट के रूप में चुना गया। ये फाइनलिस्ट नीति निर्माताओं, उद्योग जगत के नेताओं, निवेशकों और शिक्षाविदों के साथ जुड़ेंगे, साथ ही राष्ट्रीय और वैश्विक स्तर पर अपने नवाचारों को बढ़ावा देने के लिए मान्यता और सहयोग प्राप्त करेंगे।

कार्यक्रम में एस्टोनिया के राष्ट्रपति अलार कारिस और केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अंधिनी वैष्णव भी भाग ले रहे हैं। यह विश्व स्तर पर प्रसिद्ध एआई विशेषज्ञों और



अग्रणी अनुसंधान संस्थानों को एक साथ लाता है ताकि एआई-संचालित वैज्ञानिक खोज, स्वास्थ्य विचार-विमर्श किया जा सके। और ग्लोबल साउथ में अनुसंधान सहयोग पर

-पीएम मोदी और राष्ट्रपति मैक्रों के बीच हुई द्विपक्षीय बातचीत

भारत-फ्रांस के बीच कोई बाउंड्री नहीं, हमारे रिश्ते समंदर से गहरे, पहाड़ से ऊंचे...बोले पीएम मोदी



सभी पहलुओं से आपसी ट्रेड, निवेश और मोबिलिटी को नई ऊर्जा मिलेगी। और यही शेयर्ड प्रॉस्पेक्टि का रोडमैप है। इंडिया फ्रांस इंयर ऑफ इनोवेशन के लॉच से अब हम अपनी स्ट्रैटेजिक साझेदारी को पोर्टारशिप ऑफ द पीपल बनाने जा रहे हैं। क्योंकि इनोवेशन आइसोलेशन में नहीं, कोलबोरेशन से होता है। इसलिए इंडिया फ्रांस इंयर ऑफ इनोवेशन में हमारा लक्ष्य लोगों के बीच संपर्क को मजबूत करने का है।

प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, आज हम महत्वपूर्ण खनिजों, जैव प्रौद्योगिकी और एडवांस मैटेरियल्स में अपना सहयोग मजबूत

कर रहे हैं। हम स्वास्थ्य के लिए 'इंडो-फ्रेंच सेंटर फॉर एआई', 'इंडो-फ्रेंच सेंटर फॉर डिजिटल साइंस एंड टेक्नोलॉजी' और 'नेशनल सेंटर ऑफ एलार्स फॉर रिकॉलिंग इन एयरोनॉटिक्स' की शुरुआत कर रहे हैं। ये केवल संस्थान नहीं हैं, बल्कि भविष्य बनाने वाले प्लेटफॉर्म हैं। दुनिया अनिश्चितता के दौर से गुजर रही है। इसतरह के माहौल में, भारत-फ्रांस की साझेदारी वैश्विक स्थिरता के लिए एक बड़ी ताकत है।

फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रों ने कहा, मैं अपनी चौथी आधिकारिक भारत यात्रा पर आपक गर्मजोशी भरे स्वागत के लिए धन्यवाद देता हूँ

केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी और जेफी एपस्टीन के बीच कथित संबंधों को लेकर कांग्रेस ने उठाए सवाल

*** 62 ईमेल व 14 मुलाकातों के राज पर छिरे पुरी, कांग्रेस ने मांगा इस्तीफा**

नई दिल्ली (एजेंसी) । कॉरपोरेट गर्वनर्स और नीतिगत पारदर्शिता के मुद्दे पर एक बार फिर राजनीतिक पाप चढ़ गया है। केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी और अमेरिकी फाइनेंसर तथा यौन अपराधी जेफ्री एपस्टीन के बीच कथित संबंधों को लेकर कांग्रेस ने मंगलवार को गंभीर आरोप लगाए। विपक्षी दल ने दावा किया है कि 2014 से 2017 के बीच कि दोनों के बीच 62 ईमेल का आदान-प्रदान हुआ और 14 मुलाकातें हुईं। यह मामला इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इसमें एक मौजूदा केंद्रीय मंत्री की जवाबदेही और

अंतरराष्ट्रीय स्तर पर दाम्नी व्यक्ति के साथ उनके

संबंधों की प्रकृति पर सवाल उठाए गए हैं।

कांग्रेस के मीडिया व प्रचार विभाग के प्रमुख पवन खेड़ा ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में इन आकड़ों को सार्वजनिक किया। खेड़ा के अनुसार कि हरदीप पुरी ने 32 ईमेल लिखे जबकि एपस्टीन ने उन्हें 30 ईमेल भेजे। इसके अलावा, जून 2014 में एनडीए सरकार के सत्ता में आने के तुरंत बाद मुलाकातों का दौर शुरू हुआ, जो 2017 तक चला। खेड़ा ने विशिष्ट तारीखों का हवाला देते हुए पूछा कि जून 5, 6, 8 और 9, 2014 को हुई बैठकों में क्या चर्चा हुई थी? कांग्रेस नेता की ओर से सबसे अहम सवाल यह उठना गया कि जब हरदीप पुरी एक सामान्य नागरिक की हैसियत



से मिल रहे थे, तो वे एपस्टीन के साथ सरकारी

नीतियों को क्यों साझा कर रहे थे। कांग्रेस ने इस

आधार पर मंत्री के तत्काल इस्तीफे और

स्पष्टीकरण की मांग की है।

लोकसभा अध्यक्ष ने बांग्लादेश के प्रधानमंत्री तारिक रहमान के शपथ-ग्रहण समारोह में भारत का प्रतिनिधित्व किया

नई दिल्ली। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने आज ढाका में प्रधानमंत्री तारिक रहमान के नेतृत्व में गठित बांग्लादेश की नई सरकार के शपथ-ग्रहण समारोह में भाग लिया। इस अवसर पर श्री बिरला ने भारत की जनता की ओर से तारिक रहमान को हार्दिक बधाई दी। लोकसभा अध्यक्ष ने ढाका में बांग्लादेश के प्रधानमंत्री तारिक रहमान से भेंट भी की तथा उन्हें प्रधानमंत्रीश्री नरेंद्र मोदी का व्यक्तिगत पत्र सौंपा, जिसमें प्रधानमंत्री रहमान को सुविधानुसार शीघ्र भारत यात्रा के लिए आमंत्रित किया गया है। श्री बिरला ने पुनः दोहराया कि भारत बांग्लादेश के लोकतांत्रिक, प्रगतिशील और समावेशी राष्ट्र निर्माण के प्रयासों में सहयोग हेतु सदैव तत्पर है। उन्होंने दोनों पड़ोसी देशों के बीच स्थायी और सुदृढ़ साझेदारी की और गहरा करने की भारत की प्रतिबद्धता भी व्यक्त की। समारोह के अवसर पर श्री बिरला ने मालदीव के राष्ट्रपति महामहिम डॉ. मोहम्मद मुइज्जु तथा भूटान के प्रधानमंत्री महामहिम शेरिंग तोबगे सहित अन्य नेताओं से भेंट की।

‘इंडस्ट्री’ की परिभाषा की सुप्रीम कोर्ट फिर करेगा व्यापक समीक्षा, 9 जजों की पीठ होगी गठित

-ऐतिहासिक पीठ के करीब 50 साल पहले दिए फैसले पर किया जाएगा पुनर्विचार

नई दिल्ली (एजेंसी) । देश के श्रम कानूनों में प्रयुक्त शब्द 'इंडस्ट्री' की परिभाषा को लेकर एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट में व्यापक कानूनी समीक्षा होने जा रही है। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को संकेत दिया है कि इस पर विचार की जाएगी। यह पीठ औद्योगिक संबंध सहित 2020 और उससे पहले लागू औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 के तहत 'इंडस्ट्री' शब्द के दायरे को स्पष्ट करेगी।

सीजेआई की अध्यक्षता वाली पीठ, जिसमें न्यायमूर्ति जयमाल्या बागची और न्यायमूर्ति बिपिन एम पंचौली शामिल थे उन्होंने बताया कि बड़ी पीठ 17 मार्च से इस मामले की सुनवाई

शुरू करेगी और संभावना है कि बहस अगले दिन तक पूरी कर ली जाएगी। इस संदर्भ में सात न्यायाधीशों की एक ऐतिहासिक पीठ द्वारा करीब 50 साल पहले दिए गए फैसले पर पुनर्विचार किया जाएगा। 1975 में न्यायमूर्ति वी आर कृष्णान अय्यर ने एक अहम फैसले में 'इंडस्ट्री' को पहचान के लिए जो कानूनी कसौटी तय की थी, उसे अब दोबारा परखा जाएगा। खासतौर पर उस फैसले के पैरा 140 से 144 में निर्धारित सिद्धांतों की वैधता और व्याख्या पर संविधान पीठ विचार करेगी।

1975 के फैसले में अदालत ने 'टिप्पल टेस्ट' का सिद्धांत विकसित किया था। इसके अनुसार कोई भी संस्था या प्रतिष्ठान तभी

'इंडस्ट्री' माना जाएगा जब वहां नियमित और व्यवस्थित गतिविधियां संचालित होती हों, निर्योका और कर्मचारी के बीच संगठित सहयोग मौजूद हो, वस्तुओं या सेवाओं का उत्पादन अथवा वितरण इस उद्देश्य से किया जा रहा हो कि मानव की जरूरतों या इच्छाओं की पूर्ति हो सके। इस व्यापक व्याख्या के कारण कलह, अस्पताल, शैक्षणिक संस्थान और अन्य सेवा आधारित संस्थाएं भी श्रम कानूनों के दायरे में आ गई थीं। अब यह देखा जाएगा कि क्या यह व्याख्या वर्तमान कानूनी और सामाजिक संदर्भ में उपयुक्त है या नहीं।

मामले का एक अहम पहलू यह भी है कि क्या सरकार द्वारा संचालित कल्याणकारी

योजनाएं या सार्वजनिक संस्थाओं की सामाजिक सेवाएं श्रम कानूनों के तहत औद्योगिक गतिविधि मानी जा सकती हैं। अदालत यह भी तय करेगी कि राज्य के कौन से कार्य ऐसे हैं जो औद्योगिक विवाद के दायरे से बाहर रखे जा सकते हैं। अदालत ने बताया कि इस मामले में पर्याप्त केस मैनेजमेंट पहले ही हो चुका है। पक्षकारों को 28 फरवरी 2026 तक अपने अतिरिक्त या अद्यतन लिखित तर्क दखिल करने की अनुमति दी गई है। दोनों पक्षों के नोडल वकीलों को याचिकाओं, दस्तावेजों और साक्ष्यों का नया संकलन तैयार करने का निर्देश दिया है। याचिकाकर्ताओं को अपनी दलीलें रखने के लिए तीन घंटे का समय दिया गया है, जबकि प्रत्युत्तर के लिए एक अतिरिक्त घंटा तय किया है।

एआई इम्पैक्ट 2026: मानव सभ्यता के द्वार पर दस्तक देती कृत्रिम बुद्धि

(लेखक-विनोद लकियावाला)

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस भव्य आयोजन का शुभारंभ किया,तो यह केवल दीप प्रज्वलन नहीं था,बल्कि उस भविष्य का उद्घाटन था जिसमें मशीनें केवल उपकरण नहीं, बल्कि मानव निर्णय,शासन, अर्थव्यवस्था और चेतना की संरचना में सहभागी होंगी।भारत जैसे विशाल जनसंख्या वाले देश के लिए यह आयोजन एक प्रयोगशाला नहीं,बल्कि एक प्रयोग-भूमि है, जहाँ करोड़ों जीवन की दिशा तय होनी है।

नई दिल्ली में 16 से 20 फरवरी 2026 के बीच आयोजित ‘एआई इम्पैक्ट 2026’ केवल एक तकनीकी सम्मेलन नहीं,बल्कि मानव सभ्यता के इतिहास में एक नए अध्याय का उद्घोष है। जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस भव्य आयोजन का शुभारंभ किया, तो यह केवल दीप प्रज्वलन नहीं था, बल्कि उस भविष्य का उद्घाटन था जिसमें मशीनें केवल उपकरण नहीं, बल्कि मानव निर्णय,शासन, अर्थव्यवस्था और चेतना की संरचना में सहभागी होंगी।। भारत जैसे विशाल जनसंख्या वाले देश के लिए यह आयोजन एक प्रयोगशाला नहीं,बल्कि एक प्रयोग-भूमि है, जहाँ करोड़ों जीवन की दिशा तय होनी है।

प्रधानमंत्री ने अपने उद्घाटन वक्तव्य में एआई को ‘विकसित भारत’ की धुरी बताते हुए कहा कि कृत्रिम बुद्धि केवल तकनीक नहीं, बल्कि मानव क्षमता के विस्तार का माध्यम है। उनका यह कथन प्रतीकात्मक नहीं, बल्कि रणनीतिक था।भारत की जनसंख्या एक ओर भार है,तो दूसरी ओर मानव पूंजी का महासागर। एआई इम्पैक्ट 2026 इसी महासागर को दिशा देने का आह्वान है। यह आयोजन उस राष्ट्रीय आकांक्षा का मंच है जिसमें भारत केवल तकनीक का उपभोक्ता नहीं, बल्कि वैश्विक एआई नेतृत्वकर्ता बनने का संकल्प ले रहा है।एआई के संदर्भ में भारत की स्थिति अद्वितीय है। एक ओर विशाल युवा जनसंख्या, दूसरी ओर डिजिटल बुनियादी ढाँचे का तीव्र विस्तार, और तीसरी ओर राजनीतिक इच्छाशक्ति।प्रधानमंत्री मोदी का ‘मिशन एआई’ केवल प्रयोगशालाओं तक सीमित नहीं, बल्कि गॉव, खेत,कारखाने, विद्यालय और शासन प्रणाली तक विस्तारित

दृष्टि है। एआई इम्पैक्ट 2026 इस दृष्टि को वैश्विक मंच पर प्रस्तुत करने का प्रयास है।

परंतु हर तकनीकी क्रांति के साथ आशंकाओं की आँधी भी आती है। औद्योगिक क्रांति ने श्रमिक वर्ग को विस्थापित किया था, सूचना क्रांति ने ज्ञान का केंद्रीकरण तोड़ा था, और अब एआई क्रांति मानव श्रम और मानव निर्णय दोनों को चुनौती दे रही है। भारत जैसे देश में जहाँ बेरोजगारी पहले से ही सामाजिक- आर्थिक तनाव का स्रोत है,वहाँ एआई का आगमन एक नई अनिश्चितता का संकेत भी है। क्या मशीनें करोड़ों नौकरियों को निगल जाएँगी? क्या मानव श्रम अप्रासंगिक हो जाएगा? क्या निर्णय-प्रक्रिया एल्गोरिश्म के हाथों में चली जाएगी? ये प्रश्न केवल तकनीकी नहीं, बल्कि दार्शनिक और राजनीतिक भी हैं।एआई इम्पैक्ट 2026 का केंद्रीय विमर्श इसी द्वंद्व पर केंद्रित है—संभावना और शंका, सफलता और संकट,विकास और विस्थापन। प्रधानमंत्री मोदी का उद्घाटन भाषण इस द्वंद्व को स्वीकारते हुए आशावाद की ओर झुका हुआ था। उन्होंने कहा कि एआई मानव को विस्थापित नहीं, बल्कि संश्लेष करेगा।यह कथन राजनीतिक रूप से आश्चस्तकारी है, परंतु सामाजिक यथार्थ में इसे मूर्त रूप देने के लिए नीतिगत क्रांति आवश्यक है।

भारत की विशाल जनसंख्या यदि प्रशिक्षित, कौशलयुक्त और डिजिटल रूप से सशक्त होती है, तो एआई क्रांति भारत को वैश्विक शक्ति बना सकती है। किंतु यदि यह जनसंख्या तकनीकी परिवर्तन से कट जाती है,तो वही जनसंख्या सामाजिक विस्फोट का कारण भी बन सकती है।एआई इम्पैक्ट 2026 इस दोराहे पर खड़े भारत का आत्ममंथन है।मानव संसाधन के संदर्भ में एआई का प्रभाव बहुआयामी है। शिक्षा प्रणाली, स्वास्थ्य सेवाएँ, कृषि, उद्योग, प्रशासन, न्याय प्रणाली—सभी क्षेत्रों में एआई की भूमिका बढ़ रही है।भारत में डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, आधार, यूपीआई, डिजिलॉकर, और अब एआई आधारित शासन मॉडल, एक नए सामाजिक अनुबंध की रचना कर रहे हैं।मोदी का मिशन इस अनुबंध को ‘डिजिटल नागरिकता’ के रूप में परिभाषित करता है। एआई इम्पैक्ट 2026 इसी डिजिटल नागरिकता का वैश्विक विमर्श है।बेरोजगारी की आशंका को लेकर अंतरराष्ट्रीय विशेषज्ञों

की राय विभाजित है। कुछ का मानना है कि एआई करोड़ों नौकरियों को समाप्त कर देगा, जबकि अन्य का कहना है कि यह उतनी ही नई नौकरियाँ भी पैदा करेगा। भारत के संदर्भ में यह समीकरण अधिक जटिल है। यहाँ अनौपचारिक क्षेत्र, कृषि आधारित रोजगार और निम्न कौशल श्रमिकों की विशाल संख्या है। यदि एआई इन क्षेत्रों में बिना सामाजिक सुरक्षा के प्रवेश करता है, तो असमानता बढ़ेगी। एआई इम्पैक्ट 2026 में इस प्रश्न पर गहन चर्चा हो रही है कि कैसे कौशल पुनर्संरचना, जीवनपर्यंत शिक्षा और डिजिटल प्रशिक्षण के माध्यम से मानव संसाधन को एआई युग के अनुरूप ढाला जाए।

प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने उद्घाटन में ‘रिस्कल, स्केल और स्पीड’ की त्रयी पर बल दिया। उनका तर्क था कि भारत को एआई में कौशल विकसित करना होगा, उसे बड़े पैमाने पर लागू करना होगा, और वैश्विक प्रतिस्पर्धा में गति बनाए रखनी होगी। यह दृष्टि भारत को केवल तकनीकी शक्ति नहीं, बल्कि नैतिक और मानवीय एआई नेतृत्वकर्ता बनाने की आकांक्षा भी रखती है।वैश्विक संदर्भ में एआई एक भू-राजनीतिक हथियार बन चुका है।अमेरिका, चीन, यूरोप और अन्य शक्तियाँ एआई को आर्थिक, सैन्य और राजनीतिक प्रभुत्व के साधन के रूप में देख रही हैं। भारत की भूमिका अब केवल संतुलन करी नहीं,बल्कि वैकल्पिक मॉडल प्रस्तुत करने की है। एआई इम्पैक्ट 2026 में भारत ने ‘मानव-केंद्रित एआई’ की अवधारणा को प्रमुखता से रखा है। यह अवधारणा एआई को मानव गरिमा, लोकतंत्र और सामाजिक न्याय के साथ जोड़ने का प्रयास है।

सफलता की संभावना विशाल है। कृषि में सटीक खेती, स्वास्थ्य में निदान की क्रांति, शिक्षा में व्यक्तिगत शिक्षण, शासन में पारदर्शिता, उद्योग में उत्पादकता—ये सभी एआई के उपहार हैं। भारत जैसे देश में जहाँ संसाधनों की कमी और जनसंख्या की अधिकता है, वहाँ एआई संसाधनों के कुशल उपयोग का माध्यम बन सकता है। एआई इम्पैक्ट 2026 इन संभावनाओं को नीतिगत रोडमैप में बदलने का मंच है।

परंतु शंका भी उतनी ही गहरी है। डेटा की निजता, एल्गोरिश्मिक पक्षपात, निगरानी राज्य, डिजिटल

उपनिवेशवाद—ये एआई युग के अंधेरे पक्ष हैं। भारत जैसे लोकतंत्र में जहाँ नागरिक अधिकारों की रक्षा सर्वोपरि है, वहाँ एआई का अनियंत्रित प्रयोग लोकतंत्र को भी चुनौती दे सकता है। प्रधानमंत्री मोदी ने अपने भाषण में ‘ट्रस्ट और ट्रांसपैरेंसी’ पर जोर देकर इस चिंता को स्वीकार किया।एआई इम्पैक्ट 2026 इसलिए केवल तकनीकी सम्मेलन नहीं, बल्कि सभ्यता का संवाद है। यह संवाद मानव और मशीन, लोकतंत्र और एल्गोरिश्म, बाजार और समाज, शक्ति और नैतिकता के बीच है। भारत इस संवाद में एक प्राचीन सभ्यता के प्रतिनिधि के रूप में उपस्थित है, जो तकनीक को साधन मानती है, साध्य नहीं।

इस आयोजन में अंतरराष्ट्रीय विशेषज्ञों, नीति निर्माताओं, उद्योग जगत और शिक्षाविदों की उपस्थिति इस बात का संकेत है कि एआई अब किसी एक देश या कंपनी का विषय नहीं, बल्कि मानवता का साझा भविष्य है।प्रधानमंत्री मोदी का उद्घाटन भाषण भारत को इस साझा भविष्य के नैतिक मार्गदर्शक के रूप में प्रस्तुत करता है।

अंततः प्रश्न यह नहीं कि एआई आएगा या नहीं, बल्कि यह है कि मानवता उसे कैसे अपनाएगी। भारत जैसे देश के लिए यह प्रश्न और भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहाँ तकनीक केवल सुविधा नहीं, बल्कि सामाजिक न्याय का उपकरण भी हो सकती है। एआई इम्पैक्ट 2026 इस संभावना, शंका और सफलता के त्रिकोण में खड़े मानव भविष्य का चिंतन है। यह आयोजन एक चेतावनी भी है और एक आशा भी –कि यदि मानव विवेक, नीति और नैतिकता तकनीक के साथ चले, तो एआई मानव सभ्यता का विनाश नहीं, बल्कि उसका उत्कर्ष बन सकता है।एआई इम्पैक्ट 2026 के उद्घाटन सत्र के साथ ही यह स्पष्ट हो गया कि भारत एआई को केवल आर्थिक वृद्धि का उपकरण नहीं, बल्कि सामाजिक परिवर्तन का आधार बनाना चाहता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने वक्तव्य में भारत की जनसांख्यिकी को ‘डेमोग्राफिक डिविडेंड’ से ‘डिजिटल डिविडेंड’ में रूपांतरित करने का आह्वान किया। उनका संकेत स्पष्ट था—यदि युवा शक्ति को एआई कौशल से लैस किया जाए, तो भारत आने वाले दशकों में वैश्विक नवाचार का केंद्र बन सकता है।

संपादकीय

एआई से दोस्ती

भारत ने बदलती वैश्विक हवा की दिशा-दशा को पहचानते हुए देश में जिस सबसे बड़ी एआई समिट आयोजित कराने का फैसला किया, उसके सकारात्मक परिणाम सामने आने लगे हैं। इस पांच दिवसीय शिखर सम्मेलन की सार्थकता का पता इस बात से चलता है कि इसमें सौ बड़ी कंपनियों के सीईओ, बीस के करीब देशों के राष्ट्राध्यक्ष और 135 देशों के प्रतिनिधि जुटने की बात कही जा रही है। हाल के वर्षों में, दुनिया के सबसे ज्यादा युवाओं के देश भारत में एआई को लेकर जिस तरह का उत्साह व जुनून देखने को मिल रहा है, उम्मीद है कि आने वाले वर्षों में वो देश को दुनिया में एआई का हब बना ही देगा। वहीं दूसरी ओर महत्वपूर्ण बात यह भी है कि एआई भारत में आम लोगों के जीवन में बदलाव की वाहक बने। आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस यानी एआई भारत समेत दुनिया के देशों में आज सुशासन, विकास व नागरिक सेवाओं के बेहतर निस्तारण में कारगर भूमिका निभा रही है। यही वजह है कि ग्लोबल साउथ के देश हमारी ओर बड़ी उम्मीद से देख रहे हैं कि भारत द्वारा विकसित एआई के दिशा-निर्देश और नीतियां उभरती अर्थव्यवस्थाओं के लिये मददगार साबित होंगी। आज दुनिया में विकसित व धनी देश एआई को अपनी संकीर्ण आर्थिक व राजनीतिक हितों की पूर्ति का साधन बना रहे हैं, उससे गरीब व विकासशील देशों में असुरक्षाबोध पैदा हो रहा है। यह सुखद ही कि देश की राजधानी दिल्ली पांच दिन तक दुनिया में एआई कैपिटल बनी रहेगी। वहीं दूसरी ओर, 20 फरवरी तक भारत मंडपम में आयोजित की जा रही पांच दिवसीय इंडिया समिट में करीब तीन लाख लोगों का रजिस्ट्रेशन कराना, इस आयोजन की सार्थकता व सफलता को ही उजागर करता है। इसमें दो राय नहीं है कि हाल के वर्षों में भारत ने खुद को एक एआई पॉवर हाउस के रूप में विकसित करने का प्रयास किया है। साथ ही विशाल डाटा संसाधन के साथ ही एआई वर्क फोर्स को भी तैयार किया है। निस्संदेह, इंडिया समिट तकनीकी क्रांति के बीच नई संभावनाओं को तलाशने की भारत की सकारात्मक पहल है। विश्वास किया जा रहा है कि इस सम्मेलन के जरिये भारत दुनिया में एआई को जवाबदेह, स्थायी और समावेशी तकनीक के रूप में स्थापित करने का प्रयास करेगा। इसमें दो राय नहीं कि हाल के वर्षों में एआई की स्वीकार्यता व कारोबार तेजी से बढ़ा है। लेकिन विडंबना यह है कि तमाम धनी राष्ट्रों में इस तकनीक को अपना जित्र बनाने की होड़ लगी है। जो कालांतर दुनिया में पहले से ही व्याप्त आर्थिक असमानता को और ही बढ़ाएगा। सही मायनों में दुनिया में समावेशी समाज बनाने और आर्थिक विषमता को दूर करने के लिये जरूरी है कि एआई का उपयोग लोकतांत्रिक तरीके से नैतिकतापूर्ण ढंग से किया जाए। विश्वास किया जाना चाहिए कि इंडिया समिट में दुनिया के देश एआई तकनीक के सामने आने वाली चुनौतियों पर भी मंथन करेंगे। इस तथ्य से भी इनकार नहीं किया जा सकता कि एआई तेजी से दुनिया में विस्तार तो पा रही है, मगर यह तकनीक मानव जीवन के लिये कई तरह के खतरों भी पैदा कर रही है। हाल के वर्षों में दुनिया में एआई के दुरुपयोग के मामले भी तेजी से बढ़े हैं। जाहिर है इसके उपयोगकर्ताओं में इसको लेकर भरोसा कायम रहना चाहिए। उम्मीद की जानी चाहिए कि इंडिया समिट में एआई की विश्वसनीयता बनाने की दिशा में कोई सार्थक पहल होगी। जरूरी है कि एआई का कारोबार करने वाली कंपनियों की जवाबदेही भी तय की जाए।

विकास की धड़कन बना असम ब्रह्मपुत्र पर सेतु और अंडरवाटर टनल से बदलती क्षेत्रीय तस्वीर

(लेखक -कांतिलाल मांडोत)

असम की धरती पर जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुवाहाटी की जनसभा में भारत माता की जय का उद्घोष किया, तो वह केवल एक राजनीतिक नारा नहीं था, बल्कि उत्तर-पूर्व के विकास को लेकर केंद्र सरकार की प्रतिबद्धता का संदेश भी था। उनके संबोधन में संगठन की शक्ति, कार्यकर्ताओं के समर्पण और राष्ट्र निर्माण के संकल्प की झलक दिखाई दी। उन्होंने स्पष्ट कहा कि 2014 के बाद उत्तर-पूर्व को प्राथमिकता दी गई है और यह क्षेत्र अब विकास की मुख्यधारा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। असम, जो लंबे समय तक भौगोलिक दूरी और बुनियादी ढांचे की कमी के कारण पिछड़ा माना जाता था, आज बड़े प्रोजेक्ट्स के जरिए नए युग में प्रवेश कर रहा है।

प्रधानमंत्री ने ब्रह्मपुत्र नदी पर बने 6-लेन के आधुनिक पुल कुमार भास्कर वर्मा सेतु का उद्घाटन किया। लगभग 3,030 करोड़ रुपये की लागत से निर्मित यह पुल गुवाहाटी और नॉर्थ गुवाहाटी को जोड़ता है। यह पूर्वोत्तर भारत का पहला एक्स्ट्राडोइज पुल है, जो इंजीनियरिंग की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसके बन जाने से दोनों शहरों के बीच यात्रा समय घटकर मात्र सात मिनट रह जाएगा।। इससे न केवल यातायात सुगम होगा, बल्कि व्यापार, शिक्षा, स्वास्थ्य और पर्यटन को भी नई गति मिलेगी। ब्रह्मपुत्र, जो असम की जीवनरेखा है, अब विकास का सेतु बन चुकी है।

प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में यह भी उल्लेख किया कि पिछले वर्षों में उत्तर-पूर्व के 125 से अधिक महान व्यक्तित्वों को पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। इससे यह स्पष्ट होता है कि इस क्षेत्र की प्रतिभा और सांस्कृतिक समृद्धि को राष्ट्रीय मंच पर उचित पहचान मिल रही है। लंबे समय तक उपेक्षित रहे इस भूभाग

को अब देश के विकास मानचित्र में प्रमुख स्थान दिया जा रहा है।

विकास की इसी कड़ी में केंद्र सरकार ने एक और ऐतिहासिक निर्णय लिया है। प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में केंद्रीय कैबिनेट ने ब्रह्मपुत्र नदी के नीचे देश की पहली टियन-ट्यूब अंडरवाटर रेल एवं सड़क टनल को मंजूरी दी है। यह परियोजना गोहपुर और नुमाजीगढ़ के बीच बनाई जाएगी। लगभग 15.8 किलोमीटर लंबी यह टनल तकनीकी दृष्टि से अत्यंत जटिल और महत्वाकांक्षी है। पूरे प्रोजेक्ट, जिसमें अप्रोच रोड और रेलवे ट्रैक भी शामिल हैं, की लंबाई 33.7 किलोमीटर होगी और इस पर लगभग 18,600 करोड़ रुपये की लागत आएगी।

इस टनल के बन जाने से वर्तमान में 240 किलोमीटर की दूरी घटकर लगभग 34 किलोमीटर रह जाएगी। इससे न केवल समय और ईंधन की बचत होगी, बल्कि क्षेत्रीय संपर्क भी सुदृढ़ होगा। यह परियोजना सामरिक दृष्टि से भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। आपात स्थिति में सेना और आवश्यक संसाधनों की तेजी से आवाजाही संभव हो सकेगी। एक ट्यूब में सिंगल रेल ट्रैक की सुविधा होगी और ट्रेनें बिजली से संचालित होंगी। सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए इसे इस प्रकार डिजाइन किया जाएगा कि ट्रेन के गुजरने के दौरान सड़क यातायात नियंत्रित रहेगा। इसमें बैलिस्टिक ट्रैक जैसी आधुनिक तकनीक का उपयोग किया जाएगा, जो इसे अत्याधुनिक संरचना बनाता है।

इन परियोजनाओं का महत्व केवल यातायात सुविधा तक सीमित नहीं है। उत्तर-पूर्व भारत लंबे समय से भौगोलिक अलगाव और सीमित बुनियादी ढांचे के कारण आर्थिक रूप से पीछे रहा है। जब मजबूत पुल, आधुनिक सड़कें और सुरक्षित रेल नेटवर्क तैयार होते हैं, तो वे केवल दो स्थानों को नहीं जोड़ते, बल्कि संभावनाओं को जोड़ते हैं। इससे उद्योग, कृषि, पर्यटन और छोटे व्यवसायों को नई

ऊर्जा मिलती है। असम, जो प्राकृतिक संसाधनों और सांस्कृतिक विविधता से समृद्ध है, अब बेहतर संपर्क के कारण राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय बाजारों से अधिक प्रभावी ढंग से जुड़ सकेगा।

प्रधानमंत्री ने अपने भाषण में संगठन की शक्ति और कार्यकर्ताओं के योगदान का विशेष उल्लेख किया। उनका कहना था कि भारतीय जनता पार्टी जहां भी पहुंची है, वह कार्यकर्ताओं के अथक परिश्रम और राष्ट्र के प्रति समर्पण का परिणाम है। उन्होंने यह भी कहा कि राष्ट्रजीवन में परिवर्तन का आधार संगठन की शक्ति होती है। यह संदेश केवल राजनीतिक कार्यकर्ताओं के लिए नहीं, बल्कि समाज के हर वर्ग के लिए प्रेरक है।

उत्तर-पूर्व के विकास की यह नई कहानी केवल सरकारी योजनाओं का विवरण नहीं है, बल्कि विश्वास, संकल्प और क्रियान्वयन का उदाहरण है। असम में बन रहे ये बड़े प्रोजेक्ट इस बात के संकेत हैं कि अब यह क्षेत्र देश के विकास की परिधि में नहीं, बल्कि केंद्र में है। पुल और टनल जैसी संरचनाएं आने वाली पीढ़ियों के लिए अवसरों के नए द्वार खोलेंगी।

गुवाहाटी की सभा में गुंजाऊ प्रभारत माता की जयफ़्फ़ का उद्घोष केवल एक नारा नहीं, बल्कि उस भावना का प्रतीक है जो विकास, एकता और आत्मनिर्भरता की दिशा में देश को आगे बढ़ा रही है। असम और पूरा उत्तर-पूर्व अब उस परिवर्तन का साक्षी बन रहा है, जो बुनियादी ढांचे से लेकर राष्ट्रीय पहचान तक हर स्तर पर दिखाई दे रहा है। यह समय है जब ब्रह्मपुत्र की धारा के साथ विकास की धारा भी समानांतर बढ़ रही है, और उत्तर-पूर्व भारत के उज्ज्वल भविष्य की नई बातर लिखी जा रही है।

(रु 103 जलवंत टाऊनशिप पूणा बॉम्बे मार्केट रोड, नियर नन्दालय हवेली सूरत मो 99749 40324 वरिष्ठ पत्रकार,साहित्यकार स्तम्भकार)

व्यवहार से ही मिल गया सवाल का जवाब



एक दार्शनिक समस्याओं के अत्यंत सटीक समाधान बताते थे। एक बार उनके पास एक सेनापति पहुंचा और स्वर्ग-नर्क के विषय में जानकारी चाही। दार्शनिक ने उनसे पूर्ण परिचय पूछा तो उसने अपने वीरतापूर्ण कार्यों के बारे में विस्तार बताया। उसकी बातें सुनकर दार्शनिक ने कहा – शवल-सूरत से तो आप सेनापति नहीं, भिखारी लगते हैं। मुझे विश्वास नहीं होता कि आपमें हथियार उठाने की क्षमता भी होगी। दार्शनिक की अपमानजनक बातें सुनकर सेनापति को गुस्सा आ गया। उसने म्यान से तलवार निकाल ली। यह देख दार्शनिक ठहाका लगाते हुए बोले – अच्छा तो आप तलवार भी रखते हैं। यह शायद काठ की होगी। लोहे की होती तो अब तक आपके हाथ से छूटकर गिर गई होती। अब तो सेनापति आपे से बाहर हो गया।

उसकी आंखें क्रोध से लाल हो गईं और वह दार्शनिक पर हमला करने को उद्यत हो गया। तभी दार्शनिक ने गंभीर होकर कहा – बस यही नर्क है। क्रोध में उन्मत्ता होकर आपने अपना विवेक खो दिया और मेरी हत्या करने को तय्यर हो गए। दार्शनिक की बात सुनकर सेनापति ने शांत होकर तलवार म्यान में वापस रख ली। तब दार्शनिक ने कहा – विवेक जाग्रत होने पर व्यक्ति को अपनी भूलों का अहसास होने लगता है। मन शांत होने से स्थिरता आती है और दिव्य आनंद की अनुभूति होती है। यही अनुभूति स्वर्ग है। सेनापति को अपने प्रश्न का उत्तर मिल गया। सार यह है कि आत्मनियंत्रण से विवेक उपजता है, जिसके कारण अनुचित कर्म या व्यवहार पर रोक लगती है और जीवन में शांति व संतोष की अनुभूति होती है।

बांग्लादेश के जेन- जी ने वंशवाद स्वीकार किया ?

(लेखक- सनत जैन)

बांग्लादेश में 2024 के जैन-जी विद्रोह के बाद शेख हसीना की सरकार गिर गई थी। अब बांग्लादेश में नया चुनाव हो गया है। इस चुनाव में बांग्लादेश की वंशवादी पार्टी के वंशज तारिक रहमान प्रधानमंत्री पद की जिम्मेदारी ले आगे आए हैं। बांग्लादेश में युवाओं ने वंशवादी पार्टी को भारी मात्रा में समर्थन देकर सत्ता तक पहुंचाया है। विद्रोह के बाद मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व में बांग्लादेश में जो अंतरिम सरकार बनी थी, उसके बाद बांग्लादेश में कुछ हद तक सामान्य स्थिति देखने को मिली थी। तारिक रहमान के माता और पिता दोनों ही

प्रधानमंत्री बन चुके हैं। 2007 में उनके खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोप लगे थे, और उनको जेल भी हुई थी। शेख हसीना की सरकार ने उन्हें कई मामलों में आरोपी ठहराया था। बांग्लादेश में हुए विद्रोह के बाद 2024 में जब अंतरिम सरकार बनी, उस समय उनके ऊपर लगे आरोपों को समाप्त कर दिया गया था। 2026 में उनकी पार्टी ने चुनाव लड़ा और एक बड़ी जीत हासिल की। 12 फरवरी को बांग्लादेश में शांतिपूर्ण ढंग से चुनाव संपन्न हुए। शेख हसीना पर चुनाव में धांधली कराने का आरोप लगा था। उसकी तुलना में इस चुनाव में इस तरह का कोई आरोप देखने को नहीं मिला है। 2024 में शेख हसीना की मजबूत सत्ता को गिराने वाले

युवाओं के नेतृत्व ने इस चुनाव में जो परिणाम दिए हैं, उसने सभी को आश्चर्यचकित किया है। युवा बदलाव के प्रतीक होते हैं। बांग्लादेश के युवाओं ने स्वीडि शासन के लिए वंशवादी पार्टी को स्वीकार किया, जिसके ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप लगे थे। युवाओं ने आरोपों पर ध्यान न देते हुए तारिक रहमान के ऊपर जो विश्वास जताया, उससे यह बात स्पष्ट है, युवा पीढ़ी जोश में होते हुए भी होश नहीं खोती है। वर्तमान प्रधानमंत्री तारिक रहमान अभी तक कोई संवैधानिक पद पर नहीं रहे हैं। लेकिन वह पार्टी के अंदर प्रभावशाली माने जाते हैं। 2007 में शेख हसीना की सरकार ने उन्हें जेल भेजा था। उसके बाद वह इलाज के लिए

बांग्लादेश छोड़कर लंदन चले गए थे। शेख हसीना के शासनकाल में उनके ऊपर कई आरोप लगाए गए थे। 2024 में जब अंतरिम सरकार बनी तब सारे फैसले पलट दिए गए। वह 17 साल के बाद बांग्लादेश लौटे, शेख हसीना के प्रति गुस्सा और तारिक रहमान के प्रति सहानुभूति इस चुनाव में देखने को मिली है। शेख हसीना की सरकार में जिन राजनीतिक दलों को प्रतिबंधित किया गया था, वे इस चुनाव में नई भूमिका में आ गए हैं। इस समय बांग्लादेश आर्थिक एवं कूटनीतिक दबाव को झेल रहा है। बांग्लादेश अल्पविकसित देशों माने जाते हैं। 2007 में शेख हसीना इससे बाहर निकलने का लक्ष्य है। भारत सरकार ने शेख हसीना को शरण

दी है। जिसके कारण भारत और बांग्लादेश के संबंध में तनाव बना हुआ है। इसी बीच बांग्लादेश, अमेरिका-चीन और पाकिस्तान के करीब आया है। वर्तमान प्रधानमंत्री रहमान के सामने लोकतंत्र को संभालने की सबसे बड़ी चुनौती है। आर्थिक दबाव से भी उन्हें बाहर निकलना है। अमेरिका चीन और भारत के साथ संबंधों में संतुलन बनाने की चुनौती बांग्लादेश की है। जिन युवाओं ने उन्हें सत्ता के शिखर में पहुंचाया है वह भी सम्मान और अवसर मिलने की उम्मीद में है। बांग्लादेश की नई सरकार युवाओं की आकांक्षाओं पर खरा उतरगी, इस बात की आशा की जा सकती है। तारिक रहमान को प्रधानमंत्री की कुर्सी तक पहुंचाने के

लिए युवाओं और बांग्लादेश की आवाम ने उन पर जो भरोसा जताया है, यदि वह उम्मीद के अनुसार परिणाम नहीं दे पाए, तो वह ज्यादा दिनों तक सत्ता पर काबिज नहीं रह पाएंगे। युवा पीढ़ी ज्यादा समय तक इंजंजार नहीं करती है। बांग्लादेश के युवाओं ने सारी दुनिया को बता दिया है, कितनी भी मजबूत सत्ता हो उसे हटाया जा सकता है। इस चुनाव का असर निश्चित रूप से भारत के ऊपर भी देखने को मिलेगा। पिछले 12 वर्षों से यहां पर भी वंशवाद को लेकर वर्तमान सरकार गांधी परिवार और कांग्रेस को घेरने का कोई मौका नहीं छोड़ रही है, लेकिन जिस तरह की स्थिति भारत में बन रही है उसमें राहुल गांधी पूरी तरह से प्रभावी भूमिका में

सामने आए हैं। बांग्लादेश के चुनाव परिणाम निश्चित रूप से भारत की राजनीति को प्रभावित करने वाले साबित होंगे। इससे इनकार नहीं किया जा सकता है। भारत में भी जेन-जी की सक्रियता बढ़ रही है। उसका असर अब भारत में भी दिखने लगा है। 1947 के पहले से भारत, बांग्लादेश और पाकिस्तान के नागरिक एक ही संस्कृति और सोच के साथ रहते आए हैं। पाकिस्तान, बांग्लादेश और भारत में जो भी होता है, इसका असर एक दूसरे देश पर पड़ता ही है। इससे इंकार नहीं किया जा सकता है। बांग्लादेश में जो बदलाव हुआ है, इसका असर पश्चिम बंगाल और भारत में पड़ना तय माना जा रहा है।



भारत का कुल निर्यात 860 अरब डॉलर के स्तर पर पहुंचने की संभावना

अप्रैल-जनवरी 2025-26 में कुल निर्यात 720.76 अरब डॉलर रहा

नई दिल्ली । केंद्रीय वाणिज्य मंत्रालय के अनुसार चालू वित्त वर्ष 2025-26 में भारत का कुल निर्यात (वस्तु और सेवाएं) 860 अरब डॉलर तक पहुंच सकता है। इसमें सेवा निर्यात 410 अरब डॉलर के स्तर पर रहने का अनुमान है। अप्रैल-जनवरी 2025-26 में कुल निर्यात 720.76 अरब डॉलर रहा, जो पिछले वर्ष के समान अवधि के 679.02 अरब डॉलर की तुलना में 6.15 प्रतिशत अधिक है। जनवरी 2026 में वस्तु निर्यात 36.56 अरब डॉलर रहा, जो साल-दर-साल 0.6 प्रतिशत बढ़ा। प्रमुख बढ़त देने वाले उत्पादों में इंजीनियरिंग उत्पाद (10.40 अरब डॉलर, प्लस 10.37 फीसदी), पेट्रोलियम उत्पाद (3.77 अरब डॉलर, प्लस 8.55 फीसदी), मीट, डेयरी और पोल्ट्री (0.61 अरब डॉलर, प्लस 17.92 फीसदी), समुद्री उत्पाद (0.61 अरब डॉलर, प्लस 13.29 फीसदी) और लोहा एवं लौह अयस्क (0.21 अरब डॉलर, प्लस 31.54 फीसदी) शामिल हैं। अप्रैल-जनवरी 2025-26 में कुल आयात 823.41 अरब डॉलर रहा, जो पिछले साल की तुलना में बढ़ा है। जनवरी में आयात में तेजी मुख्य रूप से सोना और चांदी की कीमतों बढ़ने से हुई। इसी दौरान व्यापार घाटा बढ़कर 102.65 अरब डॉलर हो गया। जनवरी में अमेरिका को वाणिज्यिक निर्यात 6.58 अरब डॉलर तक पहुंचा, मासिक आधार पर 4.5 फीसदी की गिरावट के साथ। 7 फरवरी से अमेरिका ने भारत पर 25 प्रतिशत दंडात्मक शुल्क घटा दिया।

भारतीय कंपनियों के लिए एआई नौकरियों के बड़े अवसर लेकर आई: नैसकॉम

- नौकरियों में कटौती नहीं होगी, बल्कि कामकाज की प्रकृति बदल जाएगी

नई दिल्ली । उद्योग संगठन नैसकॉम में कृत्रिम मेधा (एआई) प्रमुख ने कहा कि एआई का तेजी से विकास भारतीय कंपनियों के लिए बड़े अवसर पैदा कर रहा है। उन्होंने स्पष्ट किया कि इससे नौकरियों में कटौती नहीं होगी, बल्कि कामकाज की प्रकृति बदल जाएगी। एआई के बढ़ते उपयोग से भूमिकाओं और कार्यों में परिवर्तन होगा, जिससे पेशेवरों की क्षमताओं की मांग बढ़ेगी। उन्होंने कहा कि भारत एआई को लागू करने और इसका लाभ उठाने के लिए कौशल निर्माण में तेजी ला रहा है। आने वाले महीनों में लगभग डेढ़ लाख लोगों को एआई आधारित विकास कार्यों के लिए प्रशिक्षित किया जाएगा। सरकार और निजी क्षेत्र मिलकर कॉलेजों के लिए आवश्यक पाठ्यक्रम तैयार कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि यह कदम भारत की वैश्विक प्रतिस्पर्धा में बढ़त सुनिश्चित करेगा। यह भी कहा कि वैश्विक स्तर पर एआई के इस्तेमाल के लिए और अधिक पेशेवरों की जरूरत है, और भारत इस मामले में एक मजबूत स्रोत है। अल्प अवधि में उतार-चढ़ाव हो सकते हैं, लेकिन लंबी अवधि में भारतीय कंपनियों को इस तकनीक से लाभ होगा।

स्पाइस लॉग फूड वर्क के शेयर में उछाल, शेयर पर निवेशकों की नजर

मुंबई । स्पाइस लॉग फूड वर्क के शेयरों में पिछले दिन करीब 5 फीसदी की तेजी देखी गई। दिन की शुरुआत 36.60 रुपए पर हुई, जबकि इंट्रा-डे हाई 40.44 रुपए रहा। दोपहर 1:40 बजे शेयर 40.40 रुपए पर था। पिछले पांच कारोबारी सत्रों में स्टॉक 24 फीसदी बढ़ा और एक महीने में 10 फीसदी से अधिक की तेजी दर्ज हुई। कंपनी का प्रदर्शन लंबी अवधि में भी आकर्षक रहा है। बीते एक साल में शेयर ने 196 फीसदी का रिटर्न दिया और पिछले पांच साल में इसमें 3,200 फीसदी से अधिक की उछाल आई, जिससे यह मल्टीबैगर् साबित हुआ। हाल ही में घोषित तिमाही रिपोर्ट में सालाना आधार पर शुद्ध लाभ 1.04 लाख रुपए से बढ़कर 2.21 लाख रुपए हुआ। हालांकि, तिमाही आधार पर पिछले तिमाही की तुलना में मुनाफा 61 फीसदी घट गया।

एनएचएआई ने दो राजमार्ग परिसंपत्तियों के मुद्रीकरण के लिए 6,220 करोड़ जुटाए

- महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश के राष्ट्रीय राजमार्ग शामिल

नई दिल्ली ।

राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) ने महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश में फैले 310.35 किलोमीटर लंबी दो राष्ट्रीय राजमार्ग परिसंपत्तियों के मुद्रीकरण के लिए राष्ट्रीय राजमार्ग अवसंरचना ट्रस्ट (एनएचआईटी)के प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया है। इसमें महाराष्ट्र में एनएच-53 का 255.97 किमी अमरावती-चिखली-तासोद खंड और आंध्र

प्रदेश में एनएच-16 का 54.38 किमी गुंडुगोलानु-चिन्ना-अवुतापल्ली खंड शामिल हैं। प्रस्ताव की स्वीकृत राशि 6,220.90 करोड़ रुपये। 'प्राधिकरण के चेयरमैन ने कहा कि देश भर में राष्ट्रीय राजमार्ग नेटवर्क के आगे विकास के लिए वित्तीय पूंजी जुटाने में आईएनवीआईटी (अवसंरचना निवेशकों के साथ, एनएचआईटी के माध्यम से मुद्रीकृत कुल परिसंपत्तियां

49,858 करोड़ रुपये होंगी। ष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा प्रायोजित एक निवेश (आईएनवीआईटी) राष्ट्रीय राजमार्ग अवसंरचना ट्रस्ट ने अब तक सीपीपीआईबी, एपीएफओ, एनएचएआई और एसबीआई समूह जैसे प्रमुख निवेशकों से चार दौर में पूंजी जुटाई है। 700 से अधिक निवेशकों के साथ, एनएचआईटी की इकाइयों का वर्तमान बाजार पूंजीकरण लगभग 28,000 करोड़ रुपये है। एनएचआईटी की इकाइयों

एनएसई और बीएसई दोनों पर सूचीबद्ध हैं। राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा मौजूदा परिसंपत्तियों के मूल्य को बढ़ाने और निजी क्षेत्र के निवेश को आकर्षित करने के प्रयासों में परिसंपत्ति मुद्रीकरण एक रणनीतिक उपकरण के रूप में उभरा है। टोल-ऑपरेट-ट्रांसफर (टोओटी) और अवसंरचना निवेश ट्रस्ट (इनवीआईटी) जैसे मॉडलों का लाभ उठाकर, एनएचएआई ने सफलतापूर्वक धन जुटाया है।

भारत की आर्थिक वृद्धि में निवेश और विस्तार के अवसर मौजूद : वित्त मंत्री

- नॉर्वे में निवेश और व्यापार सहयोग पर हुई चर्चा

नई दिल्ली । भारत की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने नॉर्वे के अपने आधिकारिक दौरे के दौरान वित्त मंत्री जेन्स स्टोलटेनबर्ग से मुलाकात की। दोनों नेताओं ने भारत में निवेश और व्यापार के बड़े अवसरों पर जोर दिया। विशेष रूप से नवीकरणीय ऊर्जा, सौर

ऊर्जा परियोजनाएं, रेंयर अर्थ प्रोसेसिंग और कार्बन कैप्चर एवं स्टोरेज जैसे क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने की संभावनाओं पर चर्चा हुई। दोनों नेताओं ने व्यापार और आर्थिक साझेदारी समझौते का लाभ उठाने की सहमति व्यक्त की। चर्चा में ब्लू ईकॉनमी, ग्रीन ईकॉनमी, साथ ही सांवेरेन वेल्थ और पेंशन फंड के माध्यम से निवेश के क्षेत्रों को बढ़ावा देने की रणनीतियों को

शामिल किया गया। स्टोलटेनबर्ग ने वित्त मंत्री को बताया कि नॉर्वे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इस वर्ष के अंत में होने वाली यात्रा का बेसब्री से इंतजार कर रहा है। उम्मीद जताई गई कि इस यात्रा से भारत-नॉर्वे द्विपक्षीय सहयोग और मजबूत होगा।

सीतारमण ने ओस्लो में वित्त मंत्री, ईएफटीए समिति और भारतीय-नॉर्वेजियन मैत्री समूह के

प्रमुख से भी मुलाकात की। उन्होंने समिति को रिफ्ट-आईएफएससी के दौरे के लिए आमंत्रित किया और इसे एक वैश्विक प्रतिस्पर्धी वित्तीय केंद्र बताते हुए निवेश के अवसरों और कर लाभों की जानकारी दी। साथ ही उन्होंने नॉर्वे के सीईओ और निवेशकों के साथ गोल्मेज चर्चा और प्रवासी भारतीय समुदाय से मिलने का कार्यक्रम भी रखा।

भारत में डिजिटल भुगतान की क्रांति, यूपीआई बना सबसे भरोसेमंद माध्यम

- कुल डिजिटल लेन-देन में लगभग 11 गुना वृद्धि दर्ज की गई

मुंबई । जहां कभी लेन-देन के लिए नकदी ही सबसे बड़ा सहारा हुआ करती थी, वहीं अब डिजिटल भुगतान आम बात हो गई है। डेबिट-क्रेडिट कार्ड के दौर के बाद मोबाइल आधारित भुगतान प्रणाली ने बाजार पर कब्जा जमा

लिया है। खासकर नेशनल पेमेंट कारपोरेशन आफ इंडिया (एनपीसीआई) द्वारा संचालित यूनाइटेड पेमेंट्स इंटरफेस (यूपीआई) ने भुगतान व्यवस्था को पूरी तरह बदल दिया है। अब यूजर्स वयूआर कोड स्कैन कर सेकेंडें में पैसे ट्रांसफर कर सकते हैं, जिससे यह सुविधा लोगों की पहली पसंद बन गई है। वित्त मंत्रालय की स्टडी के मुताबिक भारत में डिजिटल भुगतान और

संबंधित इंफ्रास्ट्रक्चर में तेजी से वृद्धि हुई है। कुल डिजिटल लेन-देन में लगभग 11 गुना वृद्धि दर्ज की गई है।

यूपीआई की हिस्सेदारी अब कुल डिजिटल भुगतान का 80 फीसदी तक पहुंच गई है। वयूआर कोड की संख्या 9.3 करोड़ से बढ़कर 65.8 करोड़ हो गई है, जबकि थर्ड-पार्टी ऐप प्रोवाइडर्स 16 से 38 तक पहुंच गए हैं, जो बढ़ती फिनटेक भागीदारी को

दर्शाता है। 18 से 25 वर्ष आयु वर्ग में यूपीआई का उपयोग 66 फीसदी तक पहुंच गया है। यह संकेत है कि नई पीढ़ी तेज, आसान और कैशलेस लेन-देन को प्राथमिकता दे रही है। यूपीआई अब कुल भुगतान लेन-देन का 57 फीसदी हिस्सा संभाल रहा है, जबकि नकदी का हिस्सा केवल 38 फीसदी है। 65 फीसदी उपयोगकर्ता दिन में कई बार डिजिटल भुगतान करते हैं।

शेयर बाजार हल्की बढ़त पर बंद

मुम्बई ।

भारतीय शेयर बाजार मंगलवार को हल्की बढ़त के साथ बंद हुआ। समाह के दूसरे ही कारोबारी दिन बाजार में ये तेजी दुनिया भर के बाजारों से मिले अच्छे संकेतों के साथ ही खरीददारी हावी रहने से आई है। इस कारण दिन भर के कारोबार के बाद 30 शेयरों वाला बीएसई सेंसेक्स 173.81 अंक बढ़कर 83,450.96 और 50 शेयरों वाला एनएसई निफटी 42.65 अंक उछलकर 25,725.40 पर बंद हुआ। आज कारोबार के दौरान ही लार्जकैप के साथ ही मिडकैप और स्मॉलकैप इंडेक्स में तेजी आई। वहीं निफ्टी मिडकैप 100 इंडेक्स 224.90 अंक बढ़कर 59,881.70 और निफ्टी स्मॉलकैप 100 इंडेक्स 95.80 अंक उछलकर 17,146.70 पर बंद हुआ।

आज सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के शेयरों में आये उछाल से बाहर ऊपर आया है। वहीं एफएमसीजी, मीडिया, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स,



ऑटो, फार्मा, पीएसई, हेल्थकेयर, इन्फ्रा लाभ में रहे । दूसरी ओर क मोडिटोज, रियल्टी, ऑयलएंडगैस और फाइनेशियल सर्विसेज के शेयरों में गिरावट रही। सेंसेक्स पैक में बीईएल, एलएडटी, इन्फोसिस, एशियन पेट्स, टाइटन, एचसीएल टेक, सन फार्मा, इंडिगो, एसबीआई, टीसीएस, पावर ग्रिड के शेयर लाभ में रहे। टाटा स्टील,

ट्रेंट, एमएंडएम, बजाज फिनसर्व, भारती एयरटेल, एक्सिस बैंक के शेयर गिरावट पर रहे। इससे पहले आज सुबह बाजार गिरावट के साथ खुले। शुरुआती कारोबार में मुनाफावसूली के चलते बाजार नीचे आया। सेंसेक्स 83,197 अंक कीगिरावट के साथ खुला। सुबह सेंसेक्स 165.35 अंक की

गिरावट के साथ 83,111.80 पर कारोबार कर रहा था। इसी तरह नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी-50 25,637 पर खुला और कुछ ही मिनटों में 25,600 के नीचे फिसल गया। बाजार सोमवार को हरे निशान पर बंद हुआ। मंगलवार को एशियाई शेयरों में मामूली बढ़त हुई।

रुपया बढ़त के साथ बंद

मुम्बई । अमेरिकी डॉलर के मुकाबले मंगलवार को भारतीय रुपया 7 पैसे की की बढ़त के साथ ही 90.67 पर बंद हुआ। आज सुबह शुरुआती कारोबार में रुपया एक पैसे की बढ़त के साथ अमेरिकी डॉलर के मुकाबले 90.73 पर पहुंच गया। वैश्विक स्तर पर कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट से घरेलू मुद्रा को बल मिला। विदेशी मुद्रा कारोबारियों ने बताया कि मजबूत डॉलर और विदेशी पूंजी की निकासी ने हालांकि स्थानीय मुद्रा की बढ़त को सीमित कर दिया। अंतरबैंक विदेशी मुद्रा विनिमय बाजार में रुपया, अमेरिकी डॉलर के मुकाबले 90.72 पर खुला। हालांकि बाद में फिसलकर 90.73 प्रति डॉलर पर आ गया जो पिछले बंद भाव से एक पैसा की बढ़त दर्शाता है। रुपया सोमवार को आठ पैसे टूटकर अमेरिकी डॉलर के मुकाबले 90.74 पर बंद हुआ था। इस बीच छह प्रमुख मुद्राओं के मुकाबले अमेरिकी डॉलर की स्थिति को दिखाने वाला डॉलर सूचकांक 0.23 प्रतिशत की बढ़त के साथ 97.14 पर रहा।



एनआरआई का भारत की ओर रुझान, स्वास्थ्य बीमा खरीद में 126 फीसदी उछाल

- कम प्रीमियम और डिजिटल सुविधा की वजह से वृद्धि दर्ज की गई



नई दिल्ली ।

डिजिटल बीमा प्लेटफॉर्म पॉलिसी बाजार की ताजा रिपोर्ट के अनुसार विदेशियों में बसे भारतीयों (एनआरआई) द्वारा भारत में खरीदी जा रही स्वास्थ्य बीमा पॉलिसियों में सालाना आधार पर 126 प्रतिशत की उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज की गई है। यह रुझान दर्शाता है कि एनआरआई अब भारतीय स्वास्थ्य बीमा को केवल आपातकालीन जरूरत के लिए नहीं, बल्कि एक प्रीमियम और दीर्घकालिक स्वास्थ्य समाधान के रूप में देख रहे हैं। रिपोर्ट के मुताबिक कम प्रीमियम, आसान डिजिटल प्रक्रिया और एआई आधारित टेलीमैडिकल जर्च जैसी सुविधाओं ने इस वृद्धि को गति दी है। जहां खाड़ी देशों में स्वास्थ्य बीमा का प्रीमियम 2000 से 3000 डॉलर तक पहुंच जाता है, वहीं भारत में समान कवरेज 120

से 300 डॉलर के बीच उपलब्ध है। कई मामलों में हवाई यात्रा का खर्च जोड़ने के बाद भी भारत में इलाज अधिक किफायती पड़ता है। संयुक्त अरब अमीरात, सऊदी अरब और कुवैत सहित खाड़ी देशों से कुल मांग का लगभग 50 प्रतिशत हिस्सा आ रहा है। यूरोप से करीब 25 प्रतिशत, जबकि अमेरिका और कनाडा से 17 प्रतिशत और माता-पिता के लिए अलग कवरेज में 60 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। इससे स्पष्ट है कि एनआरआई अपने भारत में रह रहे परिवारों को दीर्घकालिक स्वास्थ्य सुरक्षा सुनिश्चित करने पर विशेष ध्यान दे रहे हैं।

संक्षिप्त समाचार

वेनेजुएला में तेल बिक्री एक अरब डॉलर पार, अमेरिका में ही जमा होगी राशि

काराकस, एजेंसी। अमेरिकी ऊर्जा मंत्री क्रिस राइट ने पुष्टि की है कि वेनेजुएला के कच्चे तेल की बिक्री से होने वाली आमदनी अब एक अरब डॉलर से अधिक हो चुकी है और आगे से यह रकम कतर में बनाए गए अस्थायी खाते में नही, बल्कि सीधे अमेरिका के ट्रेजरी डिपार्टमेंट द्वारा नियंत्रित खाते में जमा की जाएगी। यह बदलाव ऐसे समय आया है, जब ट्रंप प्रशासन ने एक सैन्य कार्रवाई में पूर्व राष्ट्रपति निकोलस मादुरो को पकड़ने के बाद वेनेजुएला की तेल बिक्री पर सीधा नियंत्रण कर लिया है। क्रिस राइट ने एक साक्षात्कार में बताया कि शुरुआत में लगभग 500 मिलियन डॉलर की तेल बिक्री राशि कतर में खोले गए एक खाते में जमा की गई थी, जिस पर पूरे समय अमेरिकी सरकार का नियंत्रण था। डेमोक्रेट सांसदों ने पूरी व्यवस्था की पारदर्शिता और वैधता पर सवाल उठाए हैं। सीनेटर चक शुमर (डी-न्यूयॉर्क) और एडम शिफ (डी-कैलिफोर्निया) ने गुरुवार को ऐसा कानून पेश किया है, जिसके तहत गवर्नमेंट अकाउंटेंबिलिटी ऑफिस को कतर खाते का स्वतंत्र ऑडिट करने का निर्देश दिया जाएगा।

वानुअतु के उत्तरी तट पर 6.32 तीव्रता का भूकंप, खतरा नहीं

लंदन, एजेंसी। जर्मन रिसर्च सेंटर फॉर जियोसाइंसेज के अनुसार, शुक्रवार को प्रशांत महासागर में स्थित वानुअतु के उत्तरी तट पर 6.32 तीव्रता का शक्तिशाली भूकंप आया। भूकंप का केंद्र जमीनी से 10 किमी की गहराई पर था। शक्तिशाली झटकों के बावजूद, प्रशांत सुनामी चेतावनी केंद्र ने राहत की खबर दी कि इस भूकंप से सुनामी का कोई खतरा नहीं है। भूकंप के कारण किसी भी जान-माल के नुकसान की तत्काल कोई सूचना नहीं मिली है। वानुअतु रिंग ऑफ फायर क्षेत्र में स्थित है।

शांति वार्ता को लेकर यूक्रेन पर अमेरिका का भारी दबाव

वाशिंगटन, एजेंसी। अमेरिका के शांति वार्ता को आगे बढ़ाने के आह्वान के बाद से यूक्रेन दबाव में है। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की ने यह स्वीकारते हुए कहा, थोड़ा दबाव महसूस हो रहा है लेकिन यह देखना भी अहम है कि रूस क्या-क्या समझौते करता है। उन्होंने चिंता जताई कि यूक्रेन से दूर-दूर रियायतें देने को कहा जा रहा है, जबकि रूस से इस संदर्भ में कुछ नहीं कहा जाता। जेलेंस्की ने उम्मीद जताई कि जिनेवा में अमेरिका की मध्यस्थता से होने वाली शांति वार्ता गंभीर और सांशक होगी।

यूक्रेन के ओडेसा शहर पर रूसी ड्रोन हमला, एक महिला की मौत

जिनेवा, एजेंसी। मंगलवार और बुधवार को जिनेवा में होने वाली शांति वार्ता से पहले यूक्रेन के ओडेसा शहर में रूसी ड्रोन हमलों में एक बुजुर्ग महिला की मौत हो गई। यह ड्रोन एक आवासीय इमारत से टकराया था। वहीं, रूसी सीमावर्ती शहर बेलगोरोद में यूक्रेनी मिसाइल हमले में दो लोगों की मौत हो गई। रूस-यूक्रेन युद्ध के चार साल पूरे होने से ठीक पहले, अमेरिका की मध्यस्थता में मंगलवार और बुधवार को जिनेवा में नए दौर की बातचीत होगी। क्रेमलिन और यूक्रेन के राष्ट्रपति कार्यालय ने इस वार्ता की पुष्टि की है।

बांग्लादेश में एक और मंदिर को जलाया गया

ढाका, एजेंसी। बांग्लादेश के सिलहट सदर उपजिला में रविवार तड़के कुछ अज्ञात लोगों ने तारापुर चाय बागान स्थित श्री श्री गौर नित्ताई मंदिर में आग लगा दी। मंदिर की देखरेख करने वाले माला मुंडी ने बताया, आग तेजी से फैल गई। स्थानीय लोगों ने इस पर काबू पाने की कोशिश की लेकिन तब तक काफी नुकसान हो चुका था। आग के कारण भगवान कृष्ण, राधा-कृष्ण, पंचतत्व, भगवान नरसिंह और भगवान जगन्नाथ की मूर्तियों के साथ-साथ श्रीमद्भगवद् गीता, पूजा के वस्त्रों और पर्दों को नुकसान पहुंचा है।

उत्तरी इटली में हिमस्खलन में 2 स्कीयर की मौत, एक घायल

रोम, एजेंसी। रोम के अधिकारियों ने बताया कि रविवार को फ्रांस और स्विटजरलैंड के बॉर्डर के पास, मॉंट ब्लांक मैसिफ के डटली वाले हिस्से में रास्ते से हटकर हुए हिमस्खलन में दो स्कीयर की मौत हो गई और एक अन्य घायल हो गया। इटली के एल्पाइन रेस्क्यू के मुताबिक, रविवार सुबह कोउलोरो वेसेस में हुए हिमस्खलन में कम से कम तीन स्कीयर फंस गए, जो ऊपरी वैल वेनी में कोरमायूर का एक मशहूर फ्रीराइड कूट है। एजेंसी ने बताया कि पीड़ितों में से एक को गंभीर हालत में अस्पताल ले जाया गया, लेकिन बाद में उसकी मौत हो गई। पंद्रह बचाव दल, तीन कुत्तों की टुकड़ियों और दो हेलीकॉप्टरों ने खोज और बचाव के काम में हिस्सा लिया।

बहन और बेटी की लड़ाई में फंसा क्रूर तानाशाह! 13 साल की पुत्री को ‘पावर’ देने की तैयारी में किम जोंग उन

प्योंगयांग/सियोल, एजेंसी। देश पर कंट्रोल करने की लड़ाई दोनों के बीच तेज हो सकती है। किम जू एे की उम्र महज 13 साल है और चपाई है कि उसे 14 साल का होते ही किम जोंग उन की ओर से अपना उत्तराधिकारी घोषित किया जा सकता है। उन की बहन भी खुद को एक पावर सेंटर मानती रही हैं। ऐसे में संभव है कि यह संघर्ष बढ़ सकता है। दुनिया के सबसे क्रूर तानाशाहों में से एक किम जोंग उन के परिवार में ही फिलहाल झगड़ा होता दिख रहा है। साउथ कोरिया की खुफिया एजेंसी का कहना है कि किम जोंग उन की बेटी किम जू एे का नाम अगले नेता के तौर पर घोषित किया जा सकता है। ऐसी स्थिति में किम जोंग उन की बेटी का मुकाबला पावरफुल बुआ किम यो जोंग से हो सकता है। भविष्य में देश पर कंट्रोल करने की लड़ाई दोनों के बीच तेज हो सकती है। किम जू एे की उम्र महज 13 साल है और चचाई है कि उसे 14 साल का होते ही किम जोंग उन की ओर से अपना उत्तराधिकारी घोषित किया जा सकता है। उन की बहन भी खुद को एक पावर सेंटर मानती रही हैं। ऐसे में संभव है कि यह संघर्ष बढ़ सकता है। साउथ कोरिया की नेशनल इंटील्लिजेंस सर्विस ने बीते सप्ताह



बताया कि किम जू एे की उम्र 13 साल की हो गई हैं। अब उन्हें औपचारिक तौर पर उत्तराधिकारी घोषित किया जा सकता है। यह समय अहम है क्योंकि उत्तर कोरिया में इसी महीने एक बड़ा राजनीतिक आयोजन होने वाला है। इसमें किम जोंग उन बताएंगे कि देश के लिए भविष्य में क्या लक्ष्य तय किए गए हैं। इसके अलावा वह देश की सत्ता पर अपनी पकड़ मजबूत करने के लिए भी कुछ कदमों का ऐलान कर सकते हैं। इस दौरान किम जोंग उन की बेटी भी मंच पर हो सकती हैं। हाल ही में एक मीटिंग में वह अपने पिता का हाथ थामे हुए पहुंची थीं। किम जू एे को किसी सार्वजनिक आयोजन में पहली बार नवंबर 2022 में देखा गया था। तब वह एक लॉन्ग रेंज मिसाइल के परीक्षण में पहुंची थीं। इसके बाद वह

लगातार कई आयोजनों में पिता के साथ नजर आई हैं। उन्होंने हथियार फैक्ट्रियों के दौर किए हैं तो वहीं सैन्य परेडों में भी हिस्सा लिया है। यही नहीं बीते साल सितंबर में वह चीन की राजधानी बीजिंग भी पहुंची थीं। आमतौर पर उत्तर कोरिया की राजनीति में पुरुषों का ही वर्चस्व रहा है, लेकिन पहली बार किम जोंग उन बेटी को कमान दे सकते हैं। इसी उद्देश्य से उन्हें चीन ले जाया गया था ताकि उन्हें स्थापित किया जा सके और दुनिया भर में एक संदेश जाए।

क्यों इतनी पावरफुल मानी जाती हैं किम जोंग उन की बहन : किम जोंग उन की बेटी के लिए देश में कोई चुनौती नहीं है, लेकिन बुआ से ही चैलेंज मिल सकता है। दरअसल 38 वर्षीय किम यो जोंग को उन के बाद देश की दूसरी सबसे पावरफुल

शख्सियत माना जाता है। उनकी राजनीतिक पकड़ मजबूत है तो वहीं सैन्य हलकों में भी उनकी ताकत कम नहीं है। फिलहाल वह कोरिया की वर्कर्स पार्टी की सेंट्रल कमिटी में सीनियर पद पर हैं। इसके अलावा भाई की राय को भी वह काफी हद तक प्रभावित करती रही हैं। ऐसे में अब यदि किम जोंग उन की बेटी मजबूत हुई तो फिर चीजें बदल सकती हैं।

किम जोंग के परिवार में बर्बर रहा है सत्ता का संघर्ष : उत्तर कोरिया पूरी दुनिया के उनके मुल्कों में शुमार किया जाता है, जो सूचना से कटे हुए हैं। यहां के आम नागरिकों को दुनिया के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं होती। इसके अलावा दुनिया के मीडिया या लोगों की एंट्री पर भी काफी पाबंदियां हैं। मीडिया पर इस सेंसरशिप के चलते ही उत्तर कोरिया के लोग पूरी दुनिया से एक तरह से कटे हुए हैं। बता दें कि देश में सत्ता संघर्ष भी बहुत क्रूर रहा है। किम जोंग उन ने 2011 में सत्ता संभालने के बाद अपने अंकल और मेंटर रहे जांग सॉन्ग थाएक को गोलियां मरवाकर जान ले ली थी। इसके अलावा किम जोंग उन के सीतेले भाई किम जोंग नाम की भी 2017 में हत्या करा दी गई थी।

चीन में लूनर न्यू ईयर से पहले पटाखों की दुकान में विस्फोट, 8 लोगों की मौत, 2 घायल

बीजिंग, एजेंसी। पूर्वी चीन में लूनर (न्यू ईयर) से ठीक पहले पटाखों की दुकान में हुए विस्फोट और आग में 8 लोगों की मौत हो गई, जबकि 2 अन्य लोग मामूली रूप से झुलस गए। अधिकारियों ने सोमवार को इसकी पुष्टि की। यह धमाका रिवियार दोपहर जिआंगसू प्रांत के डोंगहाई काउंटी के एक गांव में हुआ। स्थानीय प्रशासन के अनुसार, एक निवासी ने दुकान के पास गलत तरीके से पटाखे जलाए, जिससे विस्फोट हो गया। घटना के कारणों की जांच जारी है।

सरकार के बयान में कहा गया कि दुकान के आसपास पटाखों की दुकाना बैन है। प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि लापरवाही से पटाखे जलाने के कारण आग भड़की और फिर विस्फोट हुआ। चीन में लूनर न्यू ईयर में पटाखे जलाना परंपरा का हिस्सा है। इसे बुरी शक्तियों को दूर भगाने का प्रतीक माना जाता है। हालांकि, हाल के वर्षों में वायु प्रदूषण और सुरक्षा कारणों से कई शहरों में पटाखों पर प्रतिबंध लगाया गया था। पिछले साल कुछ स्थानीय सरकारों ने इन प्रतिबंधों में ढील दी थी, जिससे बाजार में पटाखों की बिक्री बढ़ी।

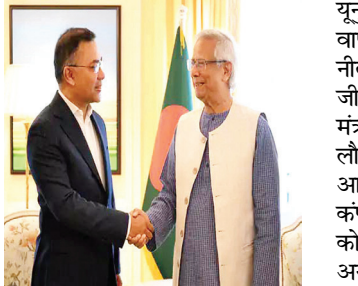
रविवार की घटना के बाद आपातकालीन प्रबंधन मंत्रालय ने सभी क्षेत्रों से पटाखों के उत्पादन, परिवहन, बिक्री और उपयोग की निगरानी कड़ी करने का आदेश दिया है। मंत्रालय ने कहा कि दुकानों के आसपास पटाखों का परीक्षण पूरी तरह से प्रतिबंधित होना चाहिए और स्थानीय सरकारों से कहा कि वे सुरक्षा की कमजोरियों को पहचान कर उन्हें दूर करें ताकि जनता सुरक्षित, मंगलमय और खुशहाल सिंग फेस्टिवल मना सके। गौरतलब है कि चीन में लूनर न्यू ईयर की रात को पटाखे जलाना एक प्राचीन परंपरा है। हाल के वर्षों में कई जगहों पर प्रदूषण को रोकने और सुरक्षा कारणों से पटाखों पर प्रतिबंध लगा दिया गया था।

बांग्लादेश-यूनूस के खिलाफ जांच आयोग बैठा सकती है रहमान सरकार

18 मंत्रियों की संपत्ति में इजाफा ; यूनुस की प्रॉपर्टी 12 करोड़ हुई, पेरिस जाने की तैयारी में

ढाका, एजेंसी। बांग्लादेश में शेख हसीना सरकार के तख्तापलट के बाद गठित मोहम्मद यूनुस सरकार के मंत्रियों की संपत्ति में उछाल आया है। सरकार के मुखिया यूनुस की संपत्ति में एक साल में लगभग 11 फीसदी की बढ़ोतरी हुई है। यूनुस की संपत्ति अब कुल साढ़े 12 करोड़ रुपए हो गई है, इसमें लगभग 1 करोड़ 30 लाख रुपए का उछाल आया है। अंतरिम सरकार के टॉप 4 मंत्रियों में सबसे ज्यादा संपत्ति की वृद्धि यूनुस की हुई है।

दूसरे नंबर पर आवास मंत्री अदिलुर रहमान की संपत्ति में 1 करोड़ 23 लाख रुपए की वृद्धि हुई। यूनुस के 21 में से 18 मंत्रियों की संपत्ति बढ़ी है। सूत्रों के अनुसार नए पीएम रहमान अंतरिम सरकार के मंत्रियों की संपत्ति में इजाफे



की जांच के लिए कमिटी गठित कर सकते हैं। इस सब के बीच यूनुस अब फिर से पेरिस में बसने की तैयारी में हैं। बता दें कि यूनुस बांग्लादेश के एकमात्र नोबेल अवॉर्ड विजेता हैं। बांग्लादेश में माइक्रो फाइनेंस के क्षेत्र में बड़ा नाम यूनुस का शेख हसीना सरकार के दौरान भ्रष्टाचार के मामले दर्ज हुए थे। लेकिन

यूनुस ने अपनी सरकार बनने पर केस वापस कर लिए थे। आइट्टी मंत्री फैज नोदरलैइस लौटे तारिक रहमान की जीत के साथ ही यूनुस सरकार में आईटी मंत्री रहे फैज अहमद तैसब नोदरलैइस के लौट गए हैं। फैज के कार्यकाल के दौरान आइट्टी सेक्टर में उनके द्वारा विदेशी कंपनियों के पक्ष में दिए गए कुछ फेसलों को लेकर आपत्तियां भी आई थीं। उन पर अनावश्यक हाई-कैपेसिटी इक्विपमेंट खरीद के लिए कुछ कंपनियों को टेंडर जारी करने के भी आरोप हैं। यूनुस सरकार में पर्यावरण मंत्री सैयदा रिजवाना का कहना है कि फैज अपने परिवार के साथ नोदरलैइस में ही रहते हैं, वे यूनुस सरकार में शामिल होने के लिए बांग्लादेश लौटे थे।

जमात प्रमुख शफीकुर से मिले



उजमा खान का नाम दिया, लेकिन हमें बताया गया कि इमरान खान की बहनें उपस्थित नहीं हो सकतीं। इसके बाद हमने अपने चचेरे भाई नोशरवान बुर्की का नाम दिया, लेकिन उसे भी अस्वीकार कर दिया गया। इमरान खान की आंखों की रोशनी 15 फीसदी बची अलीमा खान ने सवाल उठाया कि यह अस्वीकार्य है। हमारी चिंता बढ़ रही है कि हमारे परिवार के सदस्य को केवल 15% दृष्टि बची है। क्यों नहीं होने दिया जा रहा? क्या

जमात-ए-इस्लामी के अमीर से मिले तारिक रहमान; पाकिस्तान में इस्लामिक विद्वान पर जानलेवा हमला

ढाका , एजेंसी। ढाका में बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी के प्रमुख तारिक रहमान ने जमात-ए-इस्लामी के अमीर शफीकुर रहमान से मुलाकात कर चुनाव बाद हिंसा पर कार्रवाई का भरोसा दिया। 13वें संसदीय चुनाव में बीएनपी गठबंधन को 300 में से 212 सीटें मिलीं, जबकि जमात 77 सीटों के साथ प्रमुख विपक्ष बनकर उभरी। जमात ने कहा कि वह राष्ट्रीय हित में सहयोग करेगी, पर सरकार से जवाबदेही भी सुनिश्चित करेगी। तारिक रहमान के प्रधानमंत्री पद संभालने की तैयारी के बीच यह मुलाकात राजनीतिक संतुलन का संकेत मानी जा रही है।

पाकिस्तान: इंजीनियर मिर्जा पर हमले में आरोपी गिरफ्तार : पाकिस्तान के झेलम में पुलिस ने इस्लामिक स्कॉलर इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा पर हमले के आरोप में एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया। घटना उनके कुआन-ओ-सुन्नत रिसर्च अकादमी में हुई, जहां आरोपी ने कथित रूप से मला दबाने और पगड़ी उतारने की कोशिश की। पुलिस ने पाकिस्तान दंड संहिता की धारा 324 (हत्या का प्रयास) के तहत मामला दर्ज किया। मिर्जा पहले ही हमलों और ईशान्दित आरोपों का सामना कर चुके हैं तथा 2021 में उन पर जानलेवा हमला हुआ था। वह यूट्यूब पर लोकप्रिय धार्मिक व्याख्यानों के लिए जाने जाते हैं। पुलिस मामले की आगे जांच कर रही है। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमिर जेलेंस्की ने

न्यूक्लियर सुरक्षा सम्मेलन के बाद कहा कि वायु रक्षा के लिए मिसाइलें सर्वोच्च प्राथमिकता हैं। उन्होंने अमेरिका और जर्मनी का समर्थन के लिए आभार जताया तथा जर्मनी के साथ संयुक्त ड्रोन उत्पादन लाइन शुरू होने की जानकारी दी। यूके ने भी 500 मिलियन यूरो का नया एयर डिफेंस पैकेज घोषित किया। जेलेंस्की ने कहा कि अगले सप्ताह ऊर्जा अवसरचना की बहाली और उपकरणों पर बैठकें होंगी। रूस के हमलों के बीच उन्होंने नागरिकों से एयर रेड अलर्ट का पालन करने की अपील की। 17-18 फरवरी को जिनेवा में संभावित त्रिपक्षीय वार्ता की भी तैयारी है। ब्रिटेन, फ्रांस और जर्मनी समेत पांच यूरोपीय देशों द्वारा रूस पर विपक्षी नेता एलेक्सी नवलनी की हत्या करवाने के आरोपों को रूस ने नकार दिया है। रूस ने इन आरोपों को पश्चिम देशों का दृष्ट्यचार बताकर खारिज कर दिया है। रूसी विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता मारिया खजोरोवा ने कहा कि वह जांच के नतीजे सार्वजनिक होने के बाद ही कोई टिप्पणी करेगी। पांच यूरोपीय देशों ने शनिवार को आरोप लगाया था कि रूसी विपक्षी नेता एलेक्सी नवलनी की हत्या जहरीले मेड्रक के जहर से की गई थी। चीनी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने रविवार को घोषणा की कि 17 फरवरी 2026 से कनाडा और ब्रिटेन के सामान्य पासपोर्ट धारकों को चीना-मुक्त प्रवेश की सुविधा दी जाएगी।

इमरान खान के इलाज को लेकर चिंता बढ़ी, बहन अलीमा खान का आरोप- परिवार के डॉक्टर को मिलने से रोका गया

मिलने की अनुमति सुप्रीम कोर्ट ने एक मेडिकल बोर्ड बनाने का आदेश दिया और उनके बच्चों से मिलने की अनुमति 16 फरवरी से पहले देने को कहा था। हालाँकि, सरकारी अधिकारियों ने शनिवार को संकेत दिए कि इमरान को अस्पताल स्थानांतरित किया जाएगा, लेकिन रविवार दोपहर तक कोई ट्रांसफर नहीं हुआ। इमरान की बहन नूरीन नियाजी ने एक्स पर पोस्ट किया कि जेल में एम्बुलेंस आई थी, लेकिन उन्होंने कहा कि हम और खान साहिब के निजी डॉक्टरों को भरोसे में लिए बिना यह असंभव है। जेल अधीक्षक ने ट्रांसफर की खबरों को अफवाह बताते हुए कहा कि इमरान केवल जांच के लिए हैं। उन्होंने बताया कि मेडिकल टीम उनकी आंखों की जांच करेगी, विभिन्न टेस्ट करेगी और तय करेगी कि उन्हें अस्पताल स्थानांतरित किया जाए।

अगर ईरान ने समझौता नहीं किया तो उसे गंभीर परिणाम भुगतने होंगे -ट्रंप ने जिनेवा में होने वाली अहम परमाणु वार्ता से पहले दी चेतावनी



वाशिंगटन। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने जिनेवा में होने वाली अहम परमाणु वार्ता से पहले ईरान को चेतावनी भरा संदेश दिया है। ट्रंप ने कहा कि अगर ईरान ने समझौता नहीं किया तो उसे इसके गंभीर परिणाम भुगतने होंगे। ट्रंप ने कहा कि वह इस उच्चस्तरीय वार्ता प्रक्रिया में 'अप्रत्यक्ष रूप से' शामिल रहेंगे। उन्होंने कहा कि जिनेवा में होने वाली बातचीत बेहद अहम है। ट्रंप ने कहा कि 'कठिन वार्ताकार' हो, लेकिन उसकी नेतृत्व क्षमता कामजोर रही है। उन्होंने कहा कि अगर वे सही समय पर समझौता कर लेते तो हमें उनके परमाणु ठिकानों पर भी-2 विमान भेजने की जरूरत नहीं पड़ती।

मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक ट्रंप ने दावा किया कि हालिया सैन्य कार्रवाई ने पूरे भू-राजनीतिक परिपट्टि को बदल दिया और ईरान को दोबारा कूटनीति की ओर लौटने के लिए मजबूर किया। उन्होंने उम्मीद जताई कि ईरान 'ज्यादा समझदारी' दिखाएगा, क्योंकि आर्थिक और राजनीतिक दबाव उसे बातचीत की मेज पर ला रहे हैं। मिडिल ईस्ट की स्थिति पर बोलते हुए ट्रंप ने कहा कि कहीं-कहीं तनाव जरूर दिख सकता है, लेकिन कुल मिलाकर क्षेत्र में शांति कायम है।

ट्रंप ने हालिया सैन्य अभियान का बचाव करते हुए कहा कि इसकर बिना ईरान एक महीने के अंदर परमाणु हथियार बना लेता। इस औपरोशन के तहत अमेरिका ने ईरान के तीन प्रमुख परमाणु ठिकानों को निशाना बनाया था। इससे पहले अप्रैल 2025 में ईरान और अमेरिका के बीच ओमान के मस्कट और इटली के रोम में परमाणु वार्ता के दौर हुए थे, लेकिन जून 2025 में सैन्य हमलों के बाद हालात पूरी तरह बदल गए। ईरान ने इन हमलों को अंतरराष्ट्रीय कानून और संयुक्त राष्ट्र चार्टर का उल्लंघन बताया था। ईरान ने इन हमलों के बावजूद दोनों देश एक बार फिर परमाणु समझौते पर चर्चा के लिए मंगलवार को मिल रहे हैं।

बीजेपी के राहुल गांधी के खिलाफ मानहानि केस को कर्नाटक हाईकोर्ट ने किया रद्द

-कांग्रेस पार्टी ने बीजेपी सरकार पर 40 फीसदी कमीशन का लगाया था आरोप

बेंगलुरु (एजेंसी)। कर्नाटक हाईकोर्ट ने राहुल गांधी को राहत देते हुए बीजेपी की राज्य इकाई द्वारा दायर मानहानि की शिकायत को रद्द कर दिया है। जस्टिस एस सुनील दत्त यादव की एकल पीठ ने राहुल गांधी की याचिका पर यह फैसला सुनाया, जिसमें उन्होंने निचली अदालत द्वारा जारी समन और पूरी कार्यवाही को चुनौती दी थी। यह विवाद 2023 के कर्नाटक विधानसभा चुनावों के दौरान शुरू हुआ था। कांग्रेस पार्टी ने राज्य की तत्कालीन बीजेपी सरकार पर 40फीसदी कमीशन का आरोप लगाते हुए प्रमुख अखबारों में करशन रेट का कोई विज्ञापन प्रकाशित किए थे। बीजेपी ने इसे मानहानि बताते हुए राहुल गांधी, सीएम सिद्धारमेया और डिटी सीएम शिवकुमार के खिलाफ केस दर्ज कराया था। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक के मुताबिक की श्रेणी में नहीं आता, क्योंकि के उस समय किसी आधिकारिक पार्टी पद पर नहीं थे और न ही इसमें उनकी सीधी भूमिका थी। इससे पहले निचली अदालत ने उन्हें पेशी से स्थायी छूट दी थी, लेकिन अब हाईकोर्ट के इस फैसले के बाद यह मामला पूरी तरह खत्म हो गया है।

सलीम खान की तबीयत बिगड़ी, अस्पताल पहुंचे सलमान, फैस हुए चिंतित

मुंबई (एजेंसी)। सुपरस्टार और बॉलीवुड के भाईजान सलमान खान के पिता हिंदी सिनेमा के दिग्गज लेखक सलीम खान की अचानक तबीयत बिगड़ गई, जिसके बाद उन्हें मुंबई के लीलावती अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पिता की हालत की सूचना मिलते ही सलमान आनन-फानन अस्पताल पहुंचे। सलीम खान के अस्पताल में भर्ती होने की खबर फैलते ही फैंस सोशल मीडिया पर उनकी सेहत को लेकर चिंता जाहिर कर रहे हैं और जल्द स्वस्थ होने की कामना कर रहे हैं। फिलहाल परिवार की ओर से साफ नहीं किया गया है कि उन्हें किस जगह से अस्पताल में भर्ती कराया गया है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक पिता की तबीयत बिगड़ने के बीस सलमान खान का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें वे कार से उतरकर तेजी से अस्पताल के अंदर जाते दिख रहे हैं। वीडियो में उनके चेहरे पर चिंता और मायूसी साफ नजर आती है। बता दें 90 साल के सलीम खान को हिंदी सिनेमा के इतिहास के सबसे प्रभावशाली लेखकों में गिना जाता है। 1970 के दशक में जावेद अख्तर के साथ उनकी जोड़ी सलीम-जावेद ने इंडस्ट्री को कई यादगार और ब्लॉकबस्टर फिल्में दीं। इस जोड़ी ने दीवार, जंजीर और डॉन जैसी फिल्मों के जरिए बॉलीवुड के 'पट्टी रॉय गैंग' दौर को नहीं पकड़ना दी और अमिताभ बच्चन को सुपरस्टार बनाया। अभी तक सलीम खान की लेखना को लेकर परिवार की तरफ से कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं किया गया है। फैंस और इंडस्ट्री उनके जल्द स्वस्थ होने की दुआ कर रहे हैं।

जम्मू-जुवेनाइल सेंटर से 2 पाकिस्तानी सहित 3 नाबालिग फरार: मामले में 6 अधिकारी सरपंच

जम्मू (एजेंसी)। जम्मू के आरएस पुरा सेक्टर में जुवेनाइल ऑब्जेक्शन सेंटर से 2 पाकिस्तानी नागरिक सहित 3 नाबालिग फरार हुए। इसी मामले में मंगलवार को 6 पुलिसकर्मी सरपंच किए गए। नाबालिगों के सेंटर से फरार होने की घटना सीसीटीवी में रिकॉर्ड हुई थी। 22 सेंकेड के वीडियो में दिख रहा है कि शाम करीब 5.15 बजे दो नाबालिग इमग्राड कर रहे हैं। तभी सेंटर के दो कर्मचारी पास ही खड़े उन्हें समझाने की कोशिश कर रहे हैं। तभी एक पकड़ना हुआ नाबालिग पीछे से आकर कर्मचारी के सिर पर फायर कर देता है। फायर होते ही दोनों कर्मचारी पीछे हटते हैं। इसमें नाबालिग फिर से गन लोड कर दूसरा फायर करने की कोशिश करता है, लेकिन फायर नहीं होता। इसके बाद तीन नाबालिग सेंटर से भाग निकलते हैं। वहीं, जुवेनाइल सेंटर से फरार नाबालिग में एक की मां भी लापता हैं। पुलिस के मुताबिक महिला की तलाश की जा रही है। नाबालिग की फायरिंग में एसओपी विनय कुमार और हेड कांस्टेबल पर्वीन कुमार को घायल हुए हैं। उनका इलाज जारी है। नाबालिग के पास पिस्टल के घेरे पहुंची, फिलहाल इसकी जानकारी सामने नहीं आई है। पुलिस ने बताया कि जांच शुरू कर दी गई है। फरार कैदीयों को पकड़ने के लिए विशेष टीमों का गठन किया है। टीम की अलग-अलग जगहों पर छापेमारी जारी है। जुवेनाइल ऑब्जेक्शन सेंटर की सुरक्षा को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। पुलिस ने आसपास के इलाकों में चौकसी बढ़ा दी है। नागरिकों से जानकारी देने का अनुरोध किया है।

बिशनोई गैंग के गुर्ग शुभम लोनकर व उसके भाई ने रची रोहित शेंद्री के घर हमले की साजिश

मुंबई (एजेंसी)। बॉलीवुड निर्देशक रोहित शेंद्री के घर पर हुई फायरिंग मामले में मुंबई क्राइम ब्रांच ने सनसनीखेज खुलासा किया है। यह हमला लॉरेंस बिश्नोई गैंग से जुड़े महाराष्ट्र प्रमुख शुभम लोनकर और उसके भाई प्रवीण लोनकर ने करवाया था। घटना 1 फरवरी 2026 की रात हुई, जब अज्ञात हमलावरों ने रोहित शेंद्री के घर के बाहर 4-5 राउंड फायरिंग की थी। लॉरेंस बिश्नोई गैंग के गुर्ग शुभम लोनकर ने सोशल मीडिया पर हमले की जिम्मेदारी ली और निर्देशक को धमकी भी दी। पुलिस जांच में पता चल कि प्रवीण लोनकर, जो बाबा सिद्दीकी हत्याकांड में जेल में बंद है। इसके बावजूद उसने जेल से ही इस साजिश को अंजाम दिया। उसने हथियार, बाइक और आर्थिक मदद मुहैया कराई। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक क्राइम ब्रांच को शक है कि प्रवीण लोनकर ने जेल में रहते हुए ही इस पूरे अपराध की साजिश रची, जिसमें मुख्य शूटर को निर्देश दिए गए। हमले से पहले कई दिनों तक रेंकी की गई, स्कूटी पुणे से 30 हजार रुपये में खरीदी गई और मुंबई लाई गई। मुख्य आरोपी शुभम लोनकर ने पैसे और हथियार खाली किए, जबकि प्रवीण ने तीन हथियार उपलब्ध किए। आरोपियों ने सिमरन या टेलीग्राम जैसे एप्लिकेटेड ऐस से संवाद किया और बाद में डिलीट कर दिए।

चुनावी राज्यों में कांग्रेस की आंतरिक कलह बढ़ा रही मुसीबत, बगावती सुरों ने बढ़ाई नेतृत्व की टेंशन

नई दिल्ली (एजेंसी)। आगामी विधानसभा चुनावों से पहले कांग्रेस पार्टी के भीतर गहराती गुटबाजी और नेतृत्व पर उठते सवालोंने संगठन के सामने गंभीर संकट खड़ा कर दिया है। केरल, असम, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल जैसे रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण राज्यों में पार्टी के भीतर असंतोष के सुर मुखर हो रहे हैं। वरिष्ठ नेताओं की बयानबाजी और गठबंधन सहयोगियों के साथ बढ़ते तनाव ने पार्टी आलाकमान की रातों की नींद उड़ा दी है।

केरल में वरिष्ठ कांग्रेस नेता मणिशंकर अय्यर के हालिया बयान ने पार्टी को असहज कर दिया है। अय्यर ने भविष्यवाणी की है कि मुख्यमंत्री पिनारयी विजयन के नेतृत्व वाली एलडीएफ सरकार लगातार तीसरी बार सत्ता में वापसी करेगी। हालांकि पार्टी ने उनके इस बयान से पछा झाड़ लिया है, लेकिन अय्यर अपने स्टैंड पर कड़े हैं। उन्होंने तर्क दिया कि एक कांग्रेसी के रूप में वह यूडीएफ की जीत चाहते हैं, लेकिन एक गांधीवादी होने के नाते वह सच बोलने के लिए बाध्य हैं। केरल की राजनीति में हर पांच साल में सत्ता परिवर्तन की परंपरा रही है, जिसे



2021 में विजयन ने तोड़ दिया था। अब अय्यर की इस टिप्पणी ने कांग्रेस की सत्ता में वापसी की उम्मीदों को करारा झटका दिया है।

उधर असम में भी स्थिति सामान्य नहीं है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष भूपेन कुमार बोरा के इस्तीफे ने पार्टी के भीतर मंचे घमासान को सार्वजनिक कर दिया। बोरा का आरोप था कि केंद्रीय नेतृत्व उन्हें नजरअंदाज कर रहा है और राज्य इकाई में उन्हें उचित सम्मान नहीं मिल रहा है। बेहाली प्रकरण और माजुली यात्रा जैसे निर्णयों पर असंतोष जताते हुए उन्होंने महिष्कानुज खरो को

अपना त्यागपत्र भेजा था। हालांकि, राहुल गांधी के हस्तक्षेप के बाद उन्होंने इस्तीफा वापस ले लिया है, लेकिन पार्टी के भीतर मुस्लिम नेताओं की उपेक्षा और आंतरिक मतभेद अभी भी बरकरार हैं। मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने इस घटनाक्रम को कांग्रेस का गहराता संकट बताते हुए कटाक्ष किया है।

तमिलनाडु में कांग्रेस की सबसे बड़ी चुनौती सत्ताधारी डीएमके के साथ गठबंधन को बचाए रखना है। मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन ने स्पष्ट कर दिया है कि चुनाव के बाद कोई सत्ता साझेदारी नहीं

नवनीत राणा का बड़ा बयान: देश में बाबरी बनाने वालों को कब्र के लिए भी जगह नहीं मिलेगी



छतरपुर (एजेंसी)। भारतीय जनता पार्टी की नेता और पूर्व सांसद नवनीत राणा ने पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में कथित तौर पर बाबरी मस्जिद की तर्ज पर ढांचा तैयार करने की योजना को लेकर बेहद सख्त रुख अपनाया है। मध्य प्रदेश के बागेश्वर धाम में पंडित धीरेंद्र शास्त्री से मुलाकात के बाद उन्होंने एक विवादाित और आक्रामक बयान जारी किया। नवनीत राणा ने हुमायूं कबीर की योजनाओं पर प्रहार करते हुए सीधे शब्दों में कहा कि हिंदुस्तान में बाबरी बनाने की सोच रखने वालों को कब्र के लिए भी जगह नसीब नहीं होगी।

अपने संबोधन के दौरान उन्होंने धार्मिक और प्रतीकात्मक हथियारों का जिक्र करते हुए खुद को महाराष्ट्र की बेटी बताया। उन्होंने कहा कि वह मैदान में माला और तलवार, दोनों के साथ खड़ी है। संतो की शिक्षाओं का हवाला देते हुए उन्होंने जोर देकर कहा कि आज के समय में हाथों में सिर्फ माला होना पर्याप्त नहीं है, बल्कि माला के साथ-साथ भाला

होना भी उतना ही जरूरी है। उन्होंने स्पष्ट किया कि वह जरूरत पड़ने पर तलवार लेकर मैदान में उतरने से पीछे नहीं हटेंगी। मुर्शिदाबाद में बाबरी मस्जिद जैसी संरचना बनाने के प्लान के विरोध में बोलते हुए नवनीत राणा ने चेतावनी दी कि जो लोग देश के भीतर फिर से बाबरी जैसी विभाजनकारी सोच को बढ़ावा दे रहे हैं, उन्हें इसके गंभीर असर भुगतने होंगे। उन्होंने दावा किया कि ऐसे तत्वों के लिए भारत की धरती पर कोई स्थान शेष नहीं बचेगा। नवनीत राणा का यह बयान उस समय आया है जब मुर्शिदाबाद की आक्रामक बयान जारी कर दिए हैं कि वह इस मुद्दे पर किसी भी तरह के समझौते के मूड में नहीं है।

हाथों में दूषित पानी लेकर विधानसभा पहुंचे विधायक, दोषी अधिकारियों पर कार्रवाई की मांग

भोपाल (एजेंसी)। मध्य प्रदेश विधानसभा बजट सत्र के आज दूसरे दिन यानी मंगलवार को सदन की कार्यवाही शुरू होने से पहले कांग्रेस ने इंदौर के भागीरथपुरा के मुद्दे पर विरोध प्रदर्शन किया।

कांग्रेस विधायक हाथों में दूषित पानी और तख्तियां लेकर पहुंचे और सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। विपक्ष ने दोषी अधिकारियों पर कार्रवाई के साथ ही मंत्री के इस्तीफे की मांग की है। वहीं इस पर सत्ता पक्ष के विधायकों ने पलटवार भी किया है। वहीं भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस के प्रदर्शन पर पलटवार किया है। भाजपा विधायक अम्कांत शर्मा ने कहा का कांग्रेस को नैतिक रूप से इस्तीफा मांगने का कोई अधिकार नहीं है। कांग्रेस की नीतियों के कारण यह स्थिति बनी हुई है। कांग्रेस ने जो किया, हम आगे सुधारेगे।

विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने कहा कि सरकार टैक्स लेती है तो क्या स्वच्छ पानी पिलाने का जवाबदारी नहीं है। राज्यपाल के अभिभाषण में कहते हैं मेरी सरकार स्वच्छ पानी पिला रही है, तो कहाँ स्वच्छ पानी मिल रहा है ? पहले सच क्यों बहस से डर रही है। इंदौर की जनता सरकार घाट जा रही है और मंत्री कुर्सी पर बैठे हुए हैं। तत्काल मुख्यमंत्री को मंत्री से इस्तीफा लेना चाहिए। दरअसल, इंदौर में हुए पानी कांड ने मध्य



प्रदेश समेत पूरे देश को झकझोर कर रखा दिया था। भागीरथपुरा इलाके में दूषित (गंदा) पानी पीने से 25 से ज्यादा लोगों की मौत हुई थी। हालांकि सरकारी रिकॉर्ड में आंकड़े अलग हैं। इस मामले पर जमकर सियासत भी हुई थी। विपक्ष ने विरोध प्रदर्शन करते हुए दोषियों पर कार्रवाई और मंत्री से इस्तीफे की मांग की थी। वहीं दूसरी तरफ उज्जैन के तराना से कांग्रेस विधायक महेश परमार ने कहा कि इंदौर प्रशासन और भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने पूरे विश्व में शर्मसार किया है। दूषित पानी पीने से लगभग 35 से 40 लोगों की मौत हो गई। इसके बावजूद जिम्मेदार अधिकारियों पर कठोर कार्रवाई करने के बजाय उन्हें पदोन्नति देकर ऊपर भेज दिया गया। इन मामूय लोगों की मौत के लिए जो भी दोषी हैं,

उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए और पीड़ित परिवारों को न्याय मिलना चाहिए। बीजेपी को शर्म आना चाहिए।

बुधवार को पेश होगा बजट

बता दें कि एमपी विधानसभा के बजट सत्र की कार्यवाही सोमवार 16 फरवरी से शुरू हो चुकी है। जो 6 मार्च तक चलेगी। आज मंगलवार को सत्र का दूसरा दिन है। कल यानी बुधवार को विधानसभा में अनुपूरक बजट पेश किया जाएगा। इस सत्र में कुल 3478 प्रश्नों की विधानसभा को सूचनाएं, 236 ध्यानाकर्षण, 10 स्थगन प्रस्ताव, 41 अशासकीय संकल्प पेश होंगे। शून्य काल में विधानसभा में 83 सवाल होंगे।

मछुआरों के बच्चों ने 48 गांव प्लास्टिक फी कर 6 बीघ तैयार किए... अब रोज 300 पर्यटक आ रहे

कन्याकुमारी (एजेंसी)। तमिलनाडु के कन्याकुमारी जिले में हिंद महासागर के तट पर बसे 48 गांवों को मछुआरों के बच्चों ने प्लास्टिक मुक्त कर दिया है। इसके साथ ही पर्यटकों के लिए 6 बीघ तैयार किए हैं। करीब 15 किमी में फैले मछुआरों के गांवों के इन बीघों में पहले सिर्फ मछलियां ही पकड़ी जाती थीं। अब रोज यहां 250-300 पर्यटक पहुंच रहे हैं। यह सब बिना किसी एनजीओ के प्रयास या सरकारी फंड के मुम्किन हुआ है। यहां 'नेगिजी इन्न नेथल पर्डे'

(प्लास्टिक मुक्त तटीय ब्रिगेड) नाम की पूरी टीम काम कर रही है। इसमें 850 स्कूली बच्चे और 500 ग्रेजुएट हैं। ये सभी इन्हीं गांवों के हैं। ये हर वीकेंड ग्रुप बनाकर गांवों व तट साफ करते हैं। 7 सालों से चल रही इस मुहिम को इंजीनियर मेलबिन रॉबिन ने 2019 में शुरू की थी। उन्होंने 2017 के 'ओखी चक्रवात' में अपने दो भाइयों को खो दिया था। चक्रवात के बाद उन्होंने देखा कि प्लास्टिक के मलबे की वजह से तबाही ज्यादा हुई थी। इसलिए दो दस्तों के साथ

तट की सफाई शुरू की। यह ग्रुप किसी से फंडिंग या मदद नहीं मांगा। इकठ्ठा किए प्लास्टिक को बेचकर जो पैसा मिलता है, उसी से वॉलंटियर्स के लिए दस्ताने, जूते और सफाई के उपकरण खरीदते हैं। वॉलंटियर्स ने मछुआरों को तैयार किया है कि वे समुद्र में इस्तेमाल किए गए प्लास्टिक वापस जमीन पर लाएं। अब तक इस टीम ने तटों से 7,400 किलो प्लास्टिक कचरा हटाया है। इसके साथ ही चक्रवात प्रभावित क्षेत्रों में 1,200 से अधिक नारियल और जामुन के पेड़

लगाए गए हैं। मछुआरों के बच्चों की यह ब्रिगेड सिर्फ सफाई नहीं करती, बल्कि लोगों का व्यवहार बदल रही है। उन्होंने 'डोर-टू-डोर' दूध के पैकेट कलेक्शन की शुरुआत की है। पिछले साल सिर्फ तीन गांवों से ही 5 लाख से ज्यादा दूध के पैकेट इकठ्ठा कर रीसाइकिल के लिए भेजे गए। जो परिवार सबसे ज्यादा प्लास्टिक रीसाइकिल करता है, उसे यह ब्रिगेड साइकिल या अन्य जरूरी घरेलू सामान उपहार में देती है।



अमेरिकी प्रतिबंधों के घेरे में आए तीन ईरानी तेल टैंकरों को भारत ने किया जल

नई दिल्ली (एजेंसी)। अपने समुद्री क्षेत्र की सुरक्षा और अंतरराष्ट्रीय नियमों के अनुपालन को लेकर भारत पूरी तरह अलर्ट मोड में नजर आ रहा है। ताजा घटनाक्रम में भारतीय अधिकारियों ने ईरान से जुड़े उन तीन तेल टैंकरों को जल दिया है, जिन पर अमेरिका द्वारा प्रतिबंध लगाया गया था। यह कार्रवाई ऐसे समय में हुई है जब टैरिफ विवादों के कारण तनावपूर्ण रहे भारत और अमेरिका के द्विपक्षीय संबंधों में सुधार के संकेत मिल रहे हैं और अमेरिका ने हाल ही में भारत पर लगाए गए टैरिफ को घटाकर 18 प्रतिशत कर दिया है। सूत्रों के अनुसार, पकड़े गए इन टैंकरों की पहचान स्टेलर रूबी, एस्फाल्ट स्टार और अल जाफजिया के रूप में हुई है। जांच में सामने आया है कि इन जहाजों ने तटीय राज्यों के कानूनों से बचने और अपनी पहचान छिपाने के लिए बार-बार अपने नाम और विवरण बदले थे। भारतीय नौसेना और तट रक्षक बल का मुख्य उद्देश्य शिप-टू-शिप यानी एक जहाज से दूसरे जहाज में तेल के अवैध हस्तांतरण को रोकना है। अवसर तेल के मूल स्रोत को छिपाने और प्रतिबंधों से बचने के लिए अंतरराष्ट्रीय जलक्षेत्र में इस तरह की गतिविधियों को अंजाम दिया जाता है। भारतीय अधिकारियों की इस मुस्संदी का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि समुद्री सीमाओं की कड़ी निगरानी के लिए करीब 55 युद्धपोत और 10 से 12 होली विमान तैनात किए गए हैं। आंकों के मुताबिक, इन तीनों में से दो टैंकर सीधे तौर पर ईरान से जुड़े हैं। स्टेलर रूबी पर ईरान का झंडा लगा है, जबकि अल जाफजिया ने साल 2025 में ईरान से जिबूती तक तेल का परिवहन किया था। वहीं, एस्फाल्ट स्टार लंबे समय से चीन के समुद्री क्षेत्र के आसपास सक्रिय था। दिलचस्प बात यह है कि पिछले साल अमेरिकी विदेशी संपत्ति नियंत्रण कार्यालय ने ग्लोबल पीस, विल 1 और ग्लोरी स्टार 1 नामक जहाजों पर प्रतिबंध लगाया था, जिनके आईएमओ नंबर भारत द्वारा पकड़े गए इन जहाजों से मेल खाते हैं।

हिमाचल विधानसभा में हंगामा, राज्यपाल ने 2 मिनट में खत्म किया अभिभाषण

शिमला (एजेंसी)। हिमाचल प्रदेश विधानसभा के बजट सत्र का आगाज एक ऐसी असाधारण घटना के साथ हुआ जिसने राज्य के संसदीय इतिहास में नया विवाद खड़ा कर दिया है। राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल और मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की सरकार के बीच रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट (आरडीजी) और केंद्र सरकार की नीतियों को लेकर मतभेद सदन के भीतर खुलकर सामने आ गए। राज्यपाल ने दुर्लभ कदम उठाते हुए अपना अभिभाषण महज 2 मिनट 1 सेकंड में समाप्त कर दिया और सदन के पटल पर सरकार द्वारा तैयार किए गए दस्तावेज के महत्वपूर्ण हिस्सों को पढ़ने से इनकार कर दिया।

जानकारी के अनुसार, विवाद की जड़ सरकार द्वारा तैयार अभिभाषण के वे अंश थे जिनमें केंद्र सरकार और कुछ संवैधानिक संस्थाओं के कामकाज की तीखी आलोचना की गई थी। राज्यपाल ने स्पष्ट किया कि दस्तावेज के पृष्ठ 1 से 16 तक की सामग्री संस्थागत ढांचे के प्रतिकूल है और वे



संवैधानिक संस्थाओं की गरिमा को ठेस पहुंचाने वाली टिप्पणियां नहीं पढ़ सकें। इसके चलते उन्होंने केवल शुरुआती दो पैराग्राफ और अंतिम हिस्सा पढ़ा, जबकि विनयी स्थिति और केंद्र से मिलने वाली सहायता से जुड़े पैरा 3 से 16 को छोड़ दिया। सदन से बाहर निकलते समय उन्होंने विधायकों से शेष पाठ स्वयं पढ़ने को कहा, जिससे विपक्षी खेमे और सत्ता पक्ष के बीच

हलचल तेज हो गई। इस पूरे टकराव के केंद्र में रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट (आरडीजी) है। संविधान के अनुच्छेद 275(1) के तहत यह अनुदान उन राज्यों को दिया जाता है जिनकी वित्तीय स्थिति और केंद्र से मिलने वाली सहायता से जुड़े पैरा 3 से 16 को छोड़ दिया। सदन से बाहर निकलते समय उन्होंने विधायकों से शेष पाठ स्वयं पढ़ने को कहा, जिससे विपक्षी खेमे और सत्ता पक्ष के बीच

करने का निर्णय लिया, जिससे राज्य की अर्थव्यवस्था पर संकट के बादल मंडराने लगे हैं।

मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने इस घटनाक्रम पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि आरडीजी राज्य का अधिकार है और वह इसके लिए लड़ते रहेंगे। मुख्यमंत्री ने साफ किया कि यह किसी पार्टी का नहीं बल्कि पूरे प्रदेश के हक का मामला है। राज्य पर वर्तमान में संशोधित वेतन एरियर के करीब 8,500 करोड़ रुपये और महंगाई भत्ते के 5,000 करोड़ रुपये का भारी बोझ है। यदि आरडीजी बंद होती है, तो कामचलायों के वेतन और भत्तों के भुगतान पर अतिश्रुतकालीन संकट आ सकता है। राज्यपाल और सरकार के बीच हुआ यह तीखा टकराव संकेत दे रहा है कि आगामी बजट सत्र के दौरान राजभवन और सचिवालय के बीच का यह सियासी शीतयुद्ध विधानसभा की चर्चाओं को और अधिक आक्रामक बनाएगा।

असम सीएम सरमा मीरजापुर पहुंचे, राहुल गांधी को बताया मानसिक बीमार

मीरजापुर (एजेंसी)। असम के सीएम हिमंत बिस्वा सरमा ने सोमवार रात में विंध्यधाम पहुंचकर मा विंध्यवासिनी की पूजा अर्चना की। वहीं सुरक्षा व्यवस्था के मद्देनजर जिला प्रशासन व पुलिस के अधिकारी मौजूद रहे। वह वाराणसी में बाबा काशी विश्वनाथ का दर्शन पूजन करने के बाद विंध्यधाम पहुंचे। यहां विधायक समेत कई लोगों ने अंगवरुन भेटकर उनका अभिनंदन किया। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक मां का दर्शन करने के बाद हिमंत सरमा ने कहा कि राहुल गांधी मानसिक रूप से बीमार है। देश में कोई भी राहुल वादी नहीं है। महाराष्ट्र कांग्रेस अध्यक्ष द्वारा टीपू सुल्तान और छत्रपति शिवाजी को एक बराबर सम्मान दित जाने की बात पर उन्होंने कहा कि इन लोगों की बात का कोई मतलब नहीं हो सकता। एक हिंदू रक्षक थे तो दूसरा हिंदू भक्षक फिर दोनों बराबर सम्मान के अधिकारी कैसे हो सकते हैं। उन्होंने कहा कि असम की हालत बहुत खराब है।

तवांग की बर्फबारी में फंसी गाड़ी तो किरेन रिजिजू धक्का लगाते दिखे,

मंत्री का संदेश— पहाड़ी इलाकों में हर परिस्थिति के लिए रहें तैयार

तवांग (एजेंसी)। अरुणाचल प्रदेश के तवांग जिले में भारी बर्फबारी के बीच केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। इस वीडियो में वे स्थानीय लोगों और कर्मचारियों के साथ मिलकर बर्फ में फंसी एक गाड़ी को धक्का देते नजर आ रहे हैं। मंत्री ने यह वीडियो अपने आधिकारिक एक्स (पूर्व ट्विटर) अकाउंट पर साझा किया, जो अब तेजी से वायरल हो रहा है।

वीडियो में देखा जा सकता है, कि तवांग क्षेत्र में बर्फबारी इतनी तेज है कि सड़क पर वाहन मुश्किल से आगे बढ़पा रहे हैं। इसी दौरान एक वाहन बर्फ में फंस साफ गया, जिसके बाद रिजिजू खुद गाड़ी से उतरकर लोगों के साथ उसे धक्का लगाते लगे। कुछ प्रयासों के बाद वाहन को आगे बढ़ाने में सफलता मिली। इस वीडियो को साझा करते हुए रिजिजू ने पहाड़ी क्षेत्रों में यात्रा करने वाले लोगों से सतर्क रहने की अपील की। उन्होंने कहा कि तवांग जैसे दुर्गम इलाकों में मौसम



अचानक बदल सकता है, इसलिए हर परिस्थिति के लिए तैयार रहना जरूरी है। उन्होंने यात्रियों से आवश्यक सामान और सुरक्षा उपयों के साथ ही सफर करने की सलाह दी। केंद्रीय मंत्री ने सीमा सड़क संगठन (बीआरओ) की भी सराहना की, जो लगातार बर्फ हटाने और सड़कों को चालू रखने में जुटा है। उन्होंने कहा कि विपरीत मौसम परिस्थितियों में बीआरओ को चौकसी और तत्परता सराहनीय है।

तवांग क्षेत्र में पिछले कुछ दिनों से लगातार हिमपात हो रहा है, जिससे कई

प्रमुख मार्गों पर जाम की स्थिति बन गई है। बर्फ की मोटी परत के कारण छोटे और बड़े वाहनों की आवाजाही प्रभावित हुई है। बीआरओ की टीमें मशीनों और कर्मियों के साथ सड़क साफ करने में लगी हैं ताकि आवश्यक सेवाएं और यातायात सुचारु रूप से चल सके। सोशल मीडिया पर सामने आए इस वीडियो को लोग व्यापक रूप से साझा कर रहे हैं। कई यूजर्स ने इसे 'जमीनी स्तर पर सक्रिय नेता' की मिसाल बताते हुए मंत्री की सराहना की है।